गरवी गुजरात

RNI No. GUJHIN/2011/39228

GARVI GUJARAT

गरवी गुजरात

अहमदाबाद से प्रकाशित दैनिक

वर्ष : 15
अंक : 304
दि. 08.03.2026,
रविवार
पाना : 04
किंमत : 00.50 पैसा

अहमदाबाद की शाम और इतिहास का क्षण: विश्व कप की दूसरी लगातार ट्रॉफी के लिए उतरेगा भारत

जीएनएस)। अहमदाबाद का विशाल मैदान एक बार फिर इतिहास का गवाह बनने के लिए तैयार है। दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम में रविवार की शाम जब रोशनी जगमगाएगी और मैदान पर दोनों टीमें उतरेंगी, तब करोड़ों भारतीयों की धड़कनें तेज हो जाएंगी। लगभग ढाई साल पहले इसी शहर की एक रात भारतीय क्रिकेट के लिए दर्द और निराशा की याद बन गई थी। उस रात की तस्वीरों में नम आंखें, टूटी उम्मीदें और खामोश दर्शक दिखाई दे रहे थे। लेकिन समय का पहिया घूम चुका है और अब वही मैदान भारतीय टीम को इतिहास बदलने का अवसर दे रहा है। इस बार कहानी अलग हो सकती है, क्योंकि भारतीय टीम लगातार दूसरा टी-20 विश्व कप जीतने के लक्ष्य के साथ मैदान में उतरेगी। यह मुकाबला केवल एक फाइनल मैच नहीं है, बल्कि भारतीय क्रिकेट के लिए एक नए अध्याय की शुरुआत का अवसर भी है। कप्तान सूर्यकुमार यादव की युवा टीम के सामने न्यूजीलैंड जैसी मजबूत और अनुशासित टीम की चुनौती होगी। कीवी टीम अपनी जुझारू मानसिकता और बड़े मैचों में उलटफेर करने की क्षमता के लिए जानी जाती है। यही कारण है कि इस फाइनल में रोमांच चरम पर रहने वाला है। यदि भारत जीतता है तो वह लगातार दूसरा टी-20 विश्व कप जीतने वाली टीम बनेगा और तीन बार खिताब जीतने वाला पहला देश बनने का गौरव भी हासिल करेगा। वहीं अगर न्यूजीलैंड जीतता है तो वह पहली बार विश्व विजेता बनने का सपना पूरा करेगा। इस तरह दोनों ही स्थितियों में इतिहास बनना तय है।

भारतीय टीम इस समय आत्मविश्वास से भरी हुई दिखाई देती है। पूरे टूर्नामेंट में टीम ने संतुलित प्रदर्शन किया है। बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों विभागों में कई खिलाड़ियों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। हालांकि क्रिकेट का फाइनल हमेशा अलग होता है। यहाँ केवल प्रतिभा ही नहीं बल्कि दबाव झेलने की क्षमता, रणनीति और कभी-कभी किस्मत भी निर्णायक भूमिका निभाती है। भारतीय टीम के लिए सबसे बड़ा हथियार तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह माने जा रहे हैं। अहमदाबाद का यह मैदान उनके लिए लगभग घर जैसा है और उनकी गेंदबाजी में जो सटीकता और विविधता है, वह किसी भी बल्लेबाज के लिए चुनौती बन सकती है। टूर्नामेंट में अब तक उन्होंने कई महत्वपूर्ण मौकों पर विकेट लेकर टीम को मजबूती दी है। विशेष रूप से डेथ ओवरों में उनकी गेंदबाजी विपक्षी टीमों के लिए सिरदर्द बन चुकी है। न्यूजीलैंड के बल्लेबाज फिन एलन और ग्लेन फिलिप्स जैसे आक्रामक खिलाड़ी अगर बुमराह के खिलाफ खुलकर खेलना चाहेंगे तो उन्हें बेहद सावधान रहना होगा।

भारतीय बल्लेबाजी में संजू सैमसन की शानदार फॉर्म टीम के लिए सबसे बड़ा सहारा बनकर उभरी है। उन्होंने पूरे टूर्नामेंट में निरंतर रन बनाए हैं और कई बार टीम को मजबूत शुरुआत दिलाई है। उनके साथ ईशान किशन और अभिषेक शर्मा की भूमिका भी महत्वपूर्ण होगी। हालांकि अभिषेक का प्रदर्शन अब तक उम्मीदों के अनुरूप नहीं रहा है, लेकिन फाइनल जैसे बड़े मैच में एक अच्छी पारी उनके पूरे अभियान को सफल बना सकती है। कप्तान सूर्यकुमार यादव के लिए यह मुकाबला व्यक्तिगत रूप से भी बेहद महत्वपूर्ण है। पिछले दो वर्षों में उन्होंने टीम का नेतृत्व शानदार ढंग से किया है और कई युवा खिलाड़ियों को अवसर देकर एक नई टीम तैयार की है। हालांकि एक बल्लेबाज के रूप में उनका प्रदर्शन उतना प्रभावशाली नहीं रहा है जितनी उनसे उम्मीद की जाती है। ऐसे में फाइनल का यह मंच उनके लिए खुद को साबित करने का सबसे बड़ा अवसर बन सकता है। अगर इस मैच में उनका बल्ला चल जाता है तो वह अपनी कप्तानी को एक ऐतिहासिक उपलब्धि में बदल सकते हैं।

गेंदबाजी विभाग में बुमराह के अलावा अन्य गेंदबाजों को भी बेहतर प्रदर्शन करना होगा। अर्शदीप सिंह, हार्दिक पांड्या और स्पिन आक्रमण में वरुण चक्रवर्ती से टीम को काफी उम्मीदें हैं। हालांकि पिछले कुछ मैचों में चक्रवर्ती उतने प्रभावी नहीं दिखे हैं, जिसके कारण कुलदीप यादव को मौका मिलने की संभावना भी बढ़ गई है। कुलदीप की कलाई की स्पिन न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों को परेशान कर सकती है। दूसरी ओर न्यूजीलैंड की टीम को कभी भी हल्के में नहीं लिया जा सकता। क्रिकेट इतिहास में कई बार देखा गया है कि यह टीम बड़े टूर्नामेंटों में अचानक शानदार प्रदर्शन कर देती है। उनके बल्लेबाज फिन एलन और टिम साइफर्ट इस समय शानदार फॉर्म में हैं और अगर उन्हें शुरुआत में रोकना संभव नहीं हुआ तो भारत के लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं। इसके अलावा ग्लेन फिलिप्स, मिचेल सेंटनर और रचिन रविंद्र जैसे खिलाड़ी भी मैच का रुख बदलने की क्षमता रखते हैं।

न्यूजीलैंड की गेंदबाजी भी मजबूत है। लॉकी फर्ग्यूसन और मैट हेनरी जैसे तेज गेंदबाज अपनी गति और सटीकता से बल्लेबाजों को परेशान कर सकते हैं। साथ ही सेंटनर की स्पिन भारतीय बल्लेबाजों के लिए चुनौती बन सकती है। यही कारण है कि यह मुकाबला केवल कौशल का नहीं बल्कि रणनीति और धैर्य का भी होगा। इतिहास के आंकड़े भी इस मुकाबले को और दिलचस्प बनाते हैं। दोनों टीमों के बीच टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में अब तक कुल तीस मुकाबले खेले गए हैं, जिनमें भारत ने अठारह बार जीत हासिल की है जबकि न्यूजीलैंड ग्यारह बार विजयी रहा है। एक मैच टाई रहा है। हालांकि विश्व कप में न्यूजीलैंड का पलड़ा भारी रहा है और भारत अभी तक उन्हें इस टूर्नामेंट में नहीं हरा पाया है। इस बार पहली बार दोनों टीमें नॉकआउट मुकाबले में आमने-सामने होंगी, जिससे मुकाबले का महत्व और भी बढ़ गया है।

अहमदाबाद के मैदान का रिकॉर्ड भी भारत के पक्ष में दिखाई देता है। यहाँ खेले गए दस मैचों में से सात में भारतीय टीम ने जीत हासिल की है। हालांकि हाल ही में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ यहाँ एक बड़ी हार भी मिली थी, जिससे यह स्पष्ट है कि इस मैदान पर कुछ भी संभव है। न्यूजीलैंड ने यहाँ दो मैच खेले हैं और दोनों में हार का सामना करना पड़ा है, लेकिन फाइनल जैसे मैच में पुराने आंकड़े हमेशा निर्णायक नहीं होते।

भारतीय टीम के लिए यह मुकाबला केवल ट्रॉफी जीतने का नहीं बल्कि आत्मसम्मान और अधूरी कहानी को पूरा करने का भी अवसर है। कुछ साल पहले इसी शहर में एक बड़ा सपना टूट गया था और उस दर्द को करोड़ों भारतीयों ने महसूस किया था। अब वही मैदान एक नए उत्सव की उम्मीद जगा रहा है। अगर भारतीय टीम इस बार जीत हासिल करती है तो वह केवल एक ट्रॉफी नहीं बल्कि उन यादों को भी बदल देगी जो लंबे समय से क्रिकेट प्रेमियों के मन में बसी हुई हैं।

फाइनल मुकाबलों में अक्सर कहा जाता है कि साहस के साथ किस्मत का साथ भी जरूरी होता है। सेमीफाइनल में भी भारतीय टीम को कुछ ऐसे मौके मिले जिनका उसने पूरा फायदा उठाया। अगर न्यूजीलैंड की टीम भी कोई गलती करती है तो भारत उसे भुनाने की पूरी कोशिश करेगा।

संसद का गरमाता माहौल: बजट सत्र के दूसरे चरण में स्पीकर को हटाने के प्रस्ताव से बढ़ेगी राजनीतिक टकराहट

जीएनएस)। नई दिल्ली। देश की राजनीति एक बार फिर संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण के साथ गरमाने जा रही है। 9 मार्च से शुरू होने वाला यह चरण 2 अप्रैल तक चलेगा और इसकी शुरुआत ही तीखे राजनीतिक टकराव के संकेत दे रही है। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ने अपने-अपने सांसदों को सदन में अनिवार्य रूप से उपस्थित रहने के निर्देश जारी किए हैं। इसी कारण संसद के शुरुआती दिनों को बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। विशेष रूप से पहले ही दिन लोकसभा अध्यक्ष को हटाने से संबंधित प्रस्ताव आने की संभावना ने राजनीतिक वातावरण को और भी गंभीर बना दिया है।

संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण कई अहम विधायी और राजनीतिक मुद्दों के कारण चर्चा में है। सत्तारूढ़ दल और विपक्ष दोनों ही अपनी-अपनी रणनीतियों के साथ पूरी तैयारी में हैं। सांसदों को जारी किए गए श्री-लाइन व्हिप से स्पष्ट हो गया है कि आने वाले दिनों में सदन के भीतर कड़ी बहस और टकराव देखने को मिल सकता है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि संसद का यह सत्र केवल विधायी कार्यवाही तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इसमें राजनीतिक संदेश देने और अपने-अपने पक्ष को मजबूत करने की भी कोशिशें होंगी।

Indian National Congress ने अपने सांसदों को विशेष रूप से सतर्क रहने के लिए कहा है, क्योंकि शुरुआती दिनों में लोकसभा अध्यक्ष के विरुद्ध लाए गए प्रस्ताव पर चर्चा की संभावना जताई जा रही है। विपक्ष का आरोप है कि लोकसभा की कार्यवाही के दौरान अध्यक्ष ने कई मौकों पर पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाया और विपक्षी नेताओं को अपने विचार रखने के लिए पर्याप्त अवसर नहीं दिया गया। इसी आरोप के आधार पर विपक्षी दलों ने अध्यक्ष को पद से हटाने का प्रस्ताव लाने का निर्णय लिया है।

वर्तमान लोकसभा अध्यक्ष Om Birla के खिलाफ इस प्रस्ताव को विपक्ष के कई सांसदों ने समर्थन दिया है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, इस प्रस्ताव पर कुल 118 सांसदों ने हस्ताक्षर किए हैं। विपक्षी दलों का कहना है कि संसद लोकतंत्र का सर्वोच्च मंच है और यहां सभी पक्षों को समान अवसर मिलना चाहिए। उनका मानना है कि यदि अध्यक्ष की कार्यशैली निष्पक्ष न लगे तो उस पर सवाल उठाना लोकतांत्रिक अधिकार का हिस्सा है।

इस मुद्दे ने संसद के बाहर भी राजनीतिक बहस को तेज कर दिया है। कई विपक्षी नेताओं का कहना है कि संसद में विपक्ष की आवाज को दबाने की कोशिशें की जा रही हैं, जबकि सत्ता पक्ष इन आरोपों को पूरी तरह निराधार बता रहा है। सत्ता पक्ष का तर्क है कि अध्यक्ष सदन की गरिमा और नियमों के अनुसार ही कार्यवाही चलाते हैं और किसी भी प्रकार का पक्षपात नहीं किया गया है।

सत्तारूढ़ दल Bharatiya Janata Party ने भी अपने सांसदों के लिए श्री-लाइन व्हिप जारी किया है, ताकि सदन की कार्यवाही के दौरान पूरी ताकत के साथ उपस्थित रहकर सरकार का पक्ष मजबूत किया जा सके। इस व्हिप के तहत सांसदों को स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि वे 9 मार्च से 11 मार्च तक किसी भी परिस्थिति में सदन से अनुपस्थित न रहें। इससे स्पष्ट है कि सरकार भी इस मुद्दे को गंभीरता से ले रही है और किसी भी तरह की राजनीतिक असहजता से बचना चाहती है।

इस पूरे घटनाक्रम में एक दिलचस्प पहलू यह भी है कि शुरुआत में All India Trinamool Congress के 29 सांसदों ने प्रस्ताव के प्रारंभिक नोटिस पर हस्ताक्षर नहीं किए थे। हालांकि बाद में पार्टी नेतृत्व के निर्देश के बाद यह संकेत मिले हैं कि तृणमूल कांग्रेस के सांसद भी प्रस्ताव के समर्थन में मतदान कर सकते हैं। यदि ऐसा होता है तो विपक्ष का संयुक्त मोर्चा और अधिक मजबूत दिखाई देगा, हालांकि संख्या बल की स्थिति अभी भी सत्ता पक्ष के पक्ष में मानी जा रही है। संसदीय नियमों के अनुसार लोकसभा अध्यक्ष को हटाने का प्रस्ताव साधारण बहुमत से पारित किया जाता है। प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान अध्यक्ष स्वयं सदन की अध्यक्षता नहीं करते, बल्कि कोई अन्य सदस्य कार्यवाही का संचालन करता है। हालांकि अध्यक्ष को अपना पक्ष रखने का पूरा अधिकार होता है और वे इस प्रस्ताव पर मतदान भी कर सकते हैं।

तेजी से बढ़ती भारतीय संपत्ति: 2026 में देश में 308 अरबपति, वैश्विक सूची में भारत तीसरे स्थान पर

जीएनएस)। भारत की अर्थव्यवस्था लगातार नए आयाम स्थापित कर रही है और इसका स्पष्ट प्रभाव देश में संपत्ति सृजन की रफ्तार पर भी दिखाई दे रहा है। वर्ष 2026 में भारत में अरबपतियों की संख्या बढ़कर 308 हो गई है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 24 अधिक है। यह आंकड़ा न केवल देश में तेजी से बढ़ती आर्थिक गतिविधियों को दर्शाता है, बल्कि यह भी संकेत देता है कि भारतीय उद्योग, स्टार्टअप, तकनीक और निवेश के क्षेत्रों में संपत्ति निर्माण की प्रक्रिया लगातार मजबूत होती जा रही है। हुरुन रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा जारी हुरुन ग्लोबल रिच लिस्ट 2026 के अनुसार, अरबपतियों की संख्या के मामले में भारत अब अमेरिका और चीन के बाद दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश बन गया है। रिपोर्ट में बताया गया है कि भारतीय अरबपतियों की कुल संपत्ति में भी उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है। पिछले वर्ष की तुलना में उनकी कुल संपत्ति में लगभग 10 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है और यह बढ़कर लगभग 112.6 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गई है। यह आंकड़ा बताता है कि भारतीय उद्योगपतियों और उद्यमियों ने वैश्विक आर्थिक चुनौतियों के बावजूद अपने व्यवसायों का विस्तार किया है और संपत्ति सृजन की गति को बनाए रखा है। रिपोर्ट के अनुसार, इस वर्ष कुल 199 भारतीय अरबपतियों की संपत्ति में वृद्धि दर्ज की गई है। इसका अर्थ यह है कि देश के अधिकांश बड़े उद्योगपति और कारोबारी अपने कारोबार में लगातार वृद्धि कर रहे हैं। हालांकि, दूसरी ओर 109 अरबपतियों की संपत्ति में गिरावट आई है या उसमें कोई विशेष परिवर्तन नहीं हुआ है। यह स्थिति वैश्विक बाजार की अस्थिरता और कुछ क्षेत्रों में धीमी आर्थिक गति को भी दर्शाती है। फिर भी कुल मिलाकर देखा जाए तो भारत में संपत्ति निर्माण की रफ्तार सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ती दिखाई देती है। भारतीय अरबपतियों की सूची में महिलाओं की भागीदारी अभी भी अपेक्षाकृत कम है। रिपोर्ट के अनुसार कुल अरबपतियों में महिलाओं की हिस्सेदारी लगभग सात प्रतिशत है। हालांकि यह संख्या भले ही कम दिखाई देती हो, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में महिला उद्यमियों और उद्योगपतियों की संख्या में धीरे-धीरे वृद्धि हो रही है। स्टार्टअप, तकनीक, ई-कॉमर्स, स्वास्थ्य सेवा और उपभोक्ता उत्पाद जैसे क्षेत्रों में कई महिलाएं नई पहचान बना रही हैं, जिससे आने वाले वर्षों में यह अनुपात बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है। भारत में अरबपतियों के भौगोलिक वितरण पर नजर डालें तो मुंबई एक बार फिर देश का सबसे बड़ा अरबपति केंद्र बनकर उभरा है। रिपोर्ट के अनुसार देश के कुल 308 अरबपतियों में से 95 का संबंध मुंबई से है। यह आंकड़ा दर्शाता है कि भारत की आर्थिक राजधानी के रूप में मुंबई की भूमिका आज भी बेहद मजबूत है। वित्तीय संस्थान, शेयर बाजार, बड़े कॉर्पोरेट मुख्यालय और निवेश केंद्र होने के कारण मुंबई लंबे समय से देश में संपत्ति निर्माण का प्रमुख केंद्र बना हुआ है। हालांकि एशिया स्तर पर मुंबई को एक नई चुनौती का सामना करना पड़ा है। चीन का शेन्झेन शहर अब एशिया की अरबपति राजधानी बनकर उभरा है। रिपोर्ट के अनुसार शेन्झेन में कुल 133 अरबपति निवास करते हैं, जिससे वह इस मामले में एशिया में पहले स्थान पर पहुंच गया है। शेन्झेन को चीन का तकनीकी और नवाचार केंद्र माना जाता है और वहां बड़ी संख्या में तकनीकी कंपनियों और स्टार्टअप्स की सफलता ने अरबपतियों की संख्या में तेजी से वृद्धि की है।

मुंबई ने इस वर्ष 15 नए अरबपति जोड़कर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी स्थिति मजबूत की है। इस वृद्धि के कारण मुंबई ने न्यूयॉर्क सिटी और लंदन जैसे वैश्विक आर्थिक केंद्रों को पीछे छोड़ दिया है। रिपोर्ट के अनुसार न्यूयॉर्क सिटी में इस वर्ष 14 नए अरबपति जुड़े हैं, जबकि लंदन में नौ नए अरबपति शामिल हुए हैं। इस तुलना से यह स्पष्ट होता है कि भारत के आर्थिक विकास की गति विश्व के कई विकसित देशों के बराबर या उससे भी अधिक तेज हो रही है।

वैश्विक स्तर पर यदि अरबपतियों की संख्या वाले शहरों की सूची पर नजर डालें तो न्यूयॉर्क सिटी अब भी पहले स्थान पर बना हुआ है। इस शहर में कुल 146 अरबपति रहते हैं। इसके बाद चीन का शंघाई 120 अरबपतियों के साथ दूसरे स्थान पर है। बीजिंग 107 अरबपतियों के साथ तीसरे स्थान पर है, जबकि लंदन 102 अरबपतियों के साथ चौथे स्थान पर बना हुआ है। इन वैश्विक आर्थिक केंद्रों के बीच मुंबई की मजबूत उपस्थिति भारत की बढ़ती आर्थिक ताकत का संकेत देती है।

विशेषज्ञों का मानना है कि भारत में अरबपतियों की संख्या में वृद्धि का मुख्य कारण देश की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था, स्टार्टअप संस्कृति का विस्तार, डिजिटल अर्थव्यवस्था का विकास और वैश्विक निवेशकों का बढ़ता विश्वास है। पिछले एक दशक में भारत ने तकनीक, ई-कॉमर्स, वित्तीय सेवाओं, नवीकरणीय ऊर्जा, फार्मास्यूटिकल्स और बुनियादी ढांचे जैसे क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति की है। इन क्षेत्रों में तेजी से बढ़ती कंपनियों ने कई नए उद्योगपतियों और उद्यमियों को अरबपति बनने का अवसर प्रदान किया है।

सूरत के औद्योगिक क्षेत्रों में श्रमिकों के लिए अवैध आवास और स्वास्थ्य जोखिमों को लेकर चिंताएं

(छगनलाल मेवाड़ा द्वारा) सूरत। सूरत शहर समेत पूरे देश के विकास पर कोई आपत्ति या विरोध नहीं कर सकता। विकास के नाम पर हर क्षेत्र में प्रगति हो रही है, जैसे औद्योगिक क्षेत्रों में नई फैक्ट्रियां बन रही हैं, नए कारखाने लग रहे हैं, आदि, जिससे लोगों को रोजी-रोटी मिल रही है, यह बहुत अच्छी बात है। लेकिन इस रोजी-रोटी की तलाश में सूरत जैसे भीड़भाड़ वाले इलाकों में नरक जैसी जिंदगी जी रहे मजदूरों के स्वास्थ्य, आवास आदि के बारे में सोचना भी जरूरी है। अगर सिर्फ उत्पादन को ध्यान में रखकर मजदूरों के स्वास्थ्य की अनदेखी की जाएगी, तो मजदूरों के हितों की रक्षा के लिए कौन लड़ेगा? और अगर मजदूरों के स्वास्थ्य का ख्याल नहीं रखा जाएगा, तो औद्योगिक कारखानों में मेहनत कौन करेगा?

शून्य त्रुटि एजेंसी

सूरत शहर के सचिन, सूदा, कनकपुर, कंसद, पालीगम, तलंगपुर, पलसाना, कडोदरा, जोलवा, तातिथैया जैसे विभिन्न क्षेत्रों के साथ-साथ हजीरा, किम, पिपोदरा जैसे औद्योगिक क्षेत्रों में भी बड़े औद्योगिक भवन हैं और इनमें काम करने के लिए ज्यादातर मजदूर गुजरात के बाहर से आते हैं। इन उद्योगों में काम करने के लिए मजदूरों की सुविधा के लिए कारखानों के आसपास छोटे-छोटे रहने के कमरे बनाए गए हैं। जहां स्वच्छता के नाम पर गंदगी फैली रहती है। ऐसे आवासों के आसपास अपशिष्ट जल के निपटान की कोई व्यवस्था नहीं है। गंदगी के कारण कामगार वर्ग जलजनित रोगों से पीड़ित है।

कामगारों के लिए बने कमरे हवादार नहीं हैं। हर कमरे में 8 से 10 लोग रहते हैं, जहाँ साँस लेना भी मुश्किल है। ऐसी इमारतों में आने-जाने के लिए सिर्फ़ दो से ढाई फीट चौड़ी संकरी सीढ़ियाँ हैं, जिन पर एक बार में सिर्फ़ एक या दो लोग ही चल सकते हैं, जिससे कामगारों की जान को खतरा रहता है। अगर नारायण तक्षशिला जैसी कोई आग दुर्घटना हो जाए, तो कामगार इस संकरी सीढ़ी से निकलने की कोशिश में अपनी जान गंवा सकते हैं। एक तरफ तो आग से जान बचाने का प्रयास किया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ इस संकरी सीढ़ी से निकलने की धक्का-मुक्की में कामगार अपनी जान गंवा सकते हैं। जो इमारतें बन रही हैं, वे पूरी तरह से अवैध हैं, चार से पाँच मंज़िला हैं और किसी वास्तुकार या सिविल इंजीनियर के प्लान या नक्शे की मंज़ूरी के बिना बनाई जा रही हैं। जिन इमारतों में फायर एनओसी, बीयूसी, लीव स्लिप आदि कानूनी तौर पर लागू नहीं किए गए हैं, उनकी गुणवत्ता पर भी सवाल उठते हैं। इसके अलावा, ऐसी इमारतों और रिहायशी इलाकों के आसपास कूड़े के ढेर देखकर ऐसा लगता है जैसे वहाँ गाँव का मैला जमा हो। और उस कूड़े के ढेर के कारण, उस क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों के स्वास्थ्य को लेकर भी गंभीर सवाल उठते हैं, जिसके चलते गंदगी फैलने से श्रमिक बीमार पड़ जाते हैं, जानलेवा बीमारियों से पीड़ित होते हैं और अक्सर मलेरिया और डेंगू जैसे बुखारों के कारण अपनी जान गंवा देते हैं। इसलिए, सूरत नगर निगम और सुदा को बिना योजना मानचित्र के बन रही ऐसी अवैध इमारतों का तुरंत सर्वेक्षण करके उन्हें ध्वस्त कर देना चाहिए। ये इमारतें शहर में रहने वाले श्रमिकों के स्वास्थ्य को खतरे में डालकर और केवल किराया वसूलने के लिए बनाई जा रही हैं। प्रशासन को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उपर्युक्त क्षेत्रों में बिना योजना पास के कोई निर्माण कार्य न हो। अवैध रूप से निर्मित इमारतों को भी पूरी तरह से ध्वस्त कर देना चाहिए। संक्षेप में, प्रशासन को अवैध निर्माण को ध्वस्त करने में कोई कसर नहीं छोड़नी चाहिए। अन्य स्थानों पर भी बन रही अवैध नई इमारतों को तुरंत रोका जाना चाहिए और श्रमिकों के हितों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। विकास उपभोक्ता संरक्षण एवं अनुसंधान केंद्र के दक्षिण गुजरात अध्यक्ष, छगनलाल दौलतराम मेवाड़ा ने श्रमिकों के स्वास्थ्य और उनके जीवन एवं संपत्ति की रक्षा के लिए जन अपील की है।

संपादकीय

ताकि बचे बचपन

डिजिटल क्षेत्र में भारत के अग्रणी राज्य कर्नाटक ने सोलह साल से कम उम्र के बच्चों को सोशल मीडिया के घातक प्रभावों से बचाने के लिये देश में सबसे पहले अनुकरणीय पहल की है। राज्य सरकार ने 2026-27 के बजट सत्र के दौरान घोषणा की है कि किशोरवय अब सोशल मीडिया का उपयोग नहीं कर सकेंगे। यह निर्णय अभिभावकों की उस चिंता को कम करता है जो अनियंत्रित डिजिटल गतिविधियों से उत्पन्न होने वाले जोखिम से परेशान थे। जिसमें साइबर बुलिंग व साइबर धोखाधड़ी भी शामिल है। कर्नाटक की पहल के बाद आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने भी विधानसभा में घोषणा की है कि अगले नब्बे दिनों के भीतर 13 साल से कम उम्र के बच्चों द्वारा सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर रोक लगा दी जाएगी। इस तरह आंध्र प्रदेश कर्नाटक के बाद ऐसा सख्त फैसला लेने वाला दूसरा राज्य बनने जा रहा है। इस प्रकार ये दो राज्य तेजी से ऑनलाइन होती दुनिया में 'किशोरों की सुरक्षा कैसे की जाए', की वैश्विक बहस में शामिल हो गए हैं। उल्लेखनीय है कि ऐसी पहल पहले आस्ट्रेलिया और फ्रांस आदि देशों में हो चुकी है। हालांकि, इन राज्यों की पहल सराहनीय है, लेकिन इस प्रतिबंध का प्रभावी क्रियान्वयन कैसे सुनिश्चित होगा, इसका प्रारूप अभी स्पष्ट नहीं है। दरअसल, देश-दुनिया के मनोवैज्ञानिक और बाल स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने बार-बार चेतावनी दी है कि सोशल मीडिया का अनियंत्रित उपयोग किशोरों के मानसिक और भावनात्मक विकास पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है। उल्लेखनीय है कि इस चिंता का जिक्र 2025-26 के केंद्र सरकार के आर्थिक सर्वेक्षण में भी किया गया था। कर्नाटक व आंध्र प्रदेश की यह पहल तेजी से विकसित हो रहे तकनीकी परिदृश्य के प्रति एक सुरक्षात्मक दृष्टिकोण ही दर्शाती है। लेकिन यहां सवाल उठता है कि इस कार्य योजना को अमलीजामा कैसे पहनाया जाएगा? यह हकीकत जानते हुए कि आज के डिजिटल युग में, स्मार्टफोन और ऐप्स शिक्षा, संचार और दैनिक जीवन के अभिन्न अंग बन गए हैं।

यहां उल्लेखनीय है कि तमाम स्कूल असाइनमेंट और अपडेट के लिये मैसेजिंग एप्स, ऑनलाइन पोर्टल और डिजिटल प्लेटफॉर्मों पर निर्भरता बढ़ गई है। यही वजह है कि छात्रों द्वारा 'शैक्षिक' और 'सामाजिक' उपयोग के बीच अंतर करना मुश्किल साबित हो सकता है। वहीं चिंता की बात यह भी कि किशोरों की आयु का सत्यापन कैसे व्यावहारिक बनाया जा सकेगा। वहीं देखना होगा कि सोशल मीडिया को संचालित करने वाली तकनीकी कंपनियां किस हद तक इस दिशा में सहयोग करेंगी। सहयोग न मिलने पर प्रतिबंध की व्यावहारिकता पर सवालिया निशान लग सकते हैं। उन परिवारों में जहां एक ही मोबाइल फोन का परिवार के अन्य सदस्य भी उपयोग करते हैं, वहां प्रतिबंध की व्यावहारिकता पर सवाल लग सकते हैं। उल्लेखनीय है कि आस्ट्रेलिया में पहले ही सोलह साल से कम उम्र के बच्चों के लिये सोशल मीडिया के उपयोग पर प्रतिबंध लागू है। वहीं दूसरी ओर फ्रांस जैसे अन्य देश भी सख्त डिजिटल सुरक्षा नियमों को लागू करने को लेकर गंभीर हैं। इसमें दो राय नहीं कि बच्चों को बेहतर डिजिटल सुरक्षा दी जानी जरूरी है, लेकिन केवल नियमन मात्र से इस जटिल समस्या का समाधान संभव नहीं हो सकता है। इस दिशा में सार्थक परिवर्तन सरकारों, स्कूलों, तकनीकी प्लेटफॉर्मों और सबसे महत्वपूर्ण रूप से अभिभावकों के बीच एक संतुलित दृष्टिकोण पर निर्भर करेगा। हालांकि, किशोरों को सोशल मीडिया की विकृतियों से बचाने के लिये तात्कालिक पहल केंद्र सरकार की तरफ से की जाती तो उसका देशव्यापी प्रभाव होता। लेकिन इसके बावजूद यदि कर्नाटक व आंध्र प्रदेश ने इस दिशा में पहल की है तो उम्मीद की जानी चाहिए कि अन्य राज्य भी इससे प्रेरणा ले सकेंगे। फिर निश्चित तौर पर केंद्र सरकार को भी देश में एक केंद्रीय कानून लाने को बाध्य होना पड़ सकता है। वहीं केंद्र सरकार को इस मुद्दे पर विषय विशेषज्ञों और समाज के विभिन्न वर्गों से भी राय लेनी चाहिए। ऐसे वक्त में जब बच्चों का स्क्रीन टाइम एक लत के रूप में लगातार बढ़ा है तथा उनकी एकाग्रता कम होने से पढ़ाई बाधित हो रही है, तो इस संकट का समाधान केंद्र व राज्यों की प्राथमिकता होनी चाहिए।

नारी शक्ति का नया युग और वास्तविक चुनौतियां

"नये युग की समस्याएं जैसे जलवायु परिवर्तन, युद्ध, आतंकवाद, गरीबी और डिजिटल असमानता भी महिलाओं के लिए नई चुनौतियाँ खड़ी कर रही हैं। यदि इन समस्याओं पर समय रहते ध्यान नहीं दिया गया तो आने वाले दशकों में करोड़ों महिलाएँ और लड़कियाँ अत्यधिक गरीबी की ओर धकेली जा सकती हैं।

मानव सभ्यता के विकास की कथा में यदि किसी शक्ति ने सबसे अधिक सृजन किया है, तो वह नारी शक्ति है। वह जीवन की जननी है, संस्कृति की वाहक है और समाज की संवेदनशील आत्मा है। भारतीय परंपरा ने नारी को केवल एक सामाजिक भूमिका तक सीमित नहीं रखा, बल्कि उसे 'माता' के रूप में सर्वोच्च आदर दिया। 'मातृदेवो भवः' की वाणी से लेकर 'जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी' की घोषणा तक हमारी संस्कृति में नारी के प्रति श्रद्धा का अद्वितीय भाव दिखाई देता है। यही कारण है कि भारत में धरती, गौ और मातृभूमि तक को 'माता' कहकर संबोधित किया गया। किन्तु विडम्बना यह है कि जिस समाज ने नारी को देवी का दर्जा दिया, उसी समाज में आज भी नारी असुरक्षा, भेदभाव और हिंसा का सामना कर रही है। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस 2026 हमें केवल उत्सव मनाने का अवसर नहीं देता, बल्कि यह अवसर देता है कि हम नारी की वास्तविक स्थिति का गंभीर आत्ममंथन करें। विश्व स्तर पर किए गए अध्ययनों से यह स्पष्ट होता है कि नारी की स्थिति में प्रगति अवश्य हुई है, किन्तु समानता, सुरक्षा एवं स्वतंत्रता की यात्रा अभी लंबी है। विश्व आर्थिक मंच की ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2025 के अनुसार विश्व में लैंगिक समानता का लगभग 68.8 प्रतिशत अंतर ही समाप्त हो पाया है, अर्थात् अभी भी लगभग एक तिहाई अंतर शेष है। आर्थिक भागीदारी के क्षेत्र में यह अंतर सबसे अधिक है, जहाँ समानता केवल लगभग 61 प्रतिशत तक ही पहुँची है। वर्ल्ड इकनोमिक फोरम कि स्थिति बताती है कि शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में तो महिलाएँ लगभग बराबरी के स्तर तक पहुँच गई हैं, परंतु आर्थिक अवसरों और राजनीतिक नेतृत्व में अभी भी उनकी भागीदारी सीमित है। वैश्विक स्तर पर महिलाएँ कुल कार्यबल का लगभग 42 प्रतिशत ही हैं और शीर्ष प्रबंधकीय पदों पर उनकी हिस्सेदारी लगभग एक-तिहाई के आसपास है। भारत में भी स्थिति मिश्रित है। एक ओर भारतीय महिलाएँ

अंतरिक्ष, विज्ञान, सेना, राजनीति और प्रशासन में उल्लेखनीय उपलब्धियाँ प्राप्त कर रही हैं, वहीं दूसरी ओर श्रम बाजार में उनकी भागीदारी अभी भी कम है। हाल के आँकड़ों के अनुसार भारत में महिला श्रम भागीदारी दर लगभग 32 प्रतिशत है और बड़ी संख्या में महिलाएँ घरेलू दायित्वों के कारण रोजगार से बाहर रहती हैं। बिजनेस स्टैंडर्ड के यह आँकड़े केवल संख्या नहीं हैं, यह समाज की संरचना, सोच और अवसरों की असमानता को उजागर करते हैं। आज दुनिया के अनेक देशों में महिलाएँ राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, वैज्ञानिक, सैन्य अधिकारी और उद्योगपति के रूप में नेतृत्व कर रही हैं। भारत में भी राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, वैज्ञानिक और फाइटर पायलट के रूप में महिलाओं की उपस्थिति इस परिवर्तन का प्रमाण बनी है और बन रही है। किंतु इसके साथ यह भी सत्य है कि दुनिया में अभी भी केवल सीमित देशों में ही महिलाएँ सर्वोच्च राजनीतिक पदों पर हैं और समान वेतन का प्रश्न अभी भी अधूरा है। कई अंतरराष्ट्रीय अध्ययनों के अनुसार महिलाओं को समान कार्य के लिए पुरुषों की तुलना में औसतन कम वेतन मिलता है। एक और चिंताजनक तथ्य यह है कि संघर्ष, युद्ध और संकट की स्थितियों का सबसे अधिक दुष्प्रभाव महिलाओं पर पड़ता है। हाल के वैश्विक अध्ययनों के अनुसार 2024 में लगभग 67 करोड़ महिलाएँ ऐसे क्षेत्रों में रह रही थीं जो किसी न किसी प्रकार के हिंसक संघर्ष से प्रभावित थे। नये युग की समस्याएं जैसे जलवायु परिवर्तन, युद्ध, आतंकवाद, गरीबी और डिजिटल असमानता भी महिलाओं के लिए नई चुनौतियाँ खड़ी कर रही हैं। यदि इन समस्याओं पर समय रहते ध्यान नहीं दिया गया तो आने वाले दशकों में करोड़ों महिलाएँ और लड़कियाँ अत्यधिक गरीबी की ओर धकेली जा सकती हैं। इतिहास के पन्ने यह भी बताते हैं कि जब-जब समाज संकट में पड़ा, तब-तब नारी शक्ति ने असाधारण साहस का परिचय दिया। स्वतंत्रता संग्राम में रानी चेनम्मा, बेगम हजरत महल, रानी अवन्तीबाई, सरोजिनी नायडू और दुर्गा भाभी जैसी वीरांगनाओं ने यह सिद्ध किया कि नारी केवल करुणा की प्रतिमा नहीं, बल्कि संघर्ष और साहस की भी प्रतीक है। लेकिन इतिहास के इन गौरवपूर्ण अध्यायों के बावजूद सामाजिक वास्तविकता कई बार पीड़ादायक दिखाई देती है। दहेज, भ्रूण हत्या, घरेलू हिंसा, मानव तस्करी और यौन अपराध आज भी दुनिया के अनेक समाजों में मौजूद हैं। यह केवल कानून का नहीं, बल्कि सामाजिक मानसिकता का प्रश्न है। दरअसल नारी समस्या का मूल कारण केवल बाहरी संरचनाएँ नहीं हैं, बल्कि वह सोच है जिसने सदियों तक नारी को 'कमजोर' मानकर उसकी क्षमता को सीमित करने का प्रयास किया। जब समाज नारी को केवल भूमिका से जोड़ता है, व्यक्ति के रूप में नहीं देखता, तभी असमानता जन्म लेती है। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस 2026 का वैश्विक संदेश भी इसी दिशा में संकेत करता है- ''सभी महिलाओं और लड़कियों के लिए अधिकार, न्याय और वास्तविक कार्रवाई।'' यह संदेश हमें याद दिलाता है कि आज भी दुनिया में महिलाओं को पुरुषों के समान कानूनी अधिकार पूरी तरह प्राप्त नहीं हैं और औसतन उन्हें पुरुषों के मुकाबले लगभग 64 प्रतिशत ही कानूनी अधिकार प्राप्त हैं। संयुक्त राष्ट्रसंघ कि यह स्थिति हमें सोचने के लिए बाध्य करती है कि केवल कानून बनाना पर्याप्त नहीं है, बल्कि उन कानूनों को सामाजिक चेतना में बदलना भी आवश्यक है। नारी सशक्तिकरण का वास्तविक अर्थ केवल अधिकार देना नहीं है, बल्कि अवसर, सम्मान और निर्णय लेने की स्वतंत्रता देना है। शिक्षा, स्वास्थ्य, डिजिटल साक्षरता, आर्थिक स्वावलंबन और राजनीतिक भागीदारी, ये पाँच स्तंभ नारी सशक्तिकरण की वास्तविक नींव हैं। परंतु इस परिवर्तन की शुरुआत घर से ही होगी। यदि परिवार में बेटी और बेटे को समान अवसर मिलते हैं, यदि शिक्षा में भेदभाव समाप्त होता है, यदि विवाह और दहेज जैसी कुप्रथाओं को समाज स्वयं अस्वीकार करता है, तभी नारी की वास्तविक मुक्ति संभव है। महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने उल्लेखनीय कदम उठाये हैं। चाहे उज्ज्वला योजना के द्वारा उन्हें गैस सिलिंडर दिलाना हो, गावों में घरों और शौचालय का निर्माण हो या नारी शक्ति वंदन अधिनियम को संसद में पास कराना। आज दुनिया के सभी देश इस बात को मान रहे है की मोदी के नेतृत्व में भारत की महिलाएं बहुत आगे बढ़ रही है। खेल जगत से लेकर मनोरंजन जगत तक और राजनीति से लेकर सैन्य व रक्षा तक में महिलाएं बड़ी भूमिका में हैं। बात भारतीय या अभारतीय नारी की नहीं, बल्कि उसके प्रति दृष्टिकोण की है। आवश्यकता इस दृष्टिकोण को बदलने की है, जरूरत सम्पूर्ण विश्व में नारी के प्रति उपेक्षा एवं प्रताड़ना को समाप्त करने की है। इस दिवस की सार्थकता तभी है जब महिलाओं को विकास में सहभागी ही न बनाये बल्कि उनके अस्तित्व एवं अस्मिता को नौंचने की वीभत्सताओं एवं त्रासदियों पर विराम लगे, ऐसा वातावरण बनाये। नारी को भी अपने भीतर की शक्ति को पहचानना होगा। इतिहास गवाह है कि जब नारी ने अपने आत्मबल को पहचाना है, तब समाज की दिशा बदल गई है। शिक्षा और आत्मविश्वास नारी के लिए वही भूमिका निभाते हैं जो प्रकाश अंधकार के लिए करता है। आज की नारी केवल अधिकारों की मांग करने वाली नहीं, बल्कि परिवर्तन की निर्माता है। वह विज्ञान में शोध कर रही है, आकाश में विमान उड़ा रही है, संसद में कानून बना रही है, और समाज में नेतृत्व कर रही है। फिर भी हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि नारी सम्मान का प्रश्न केवल महिलाओं का नहीं, बल्कि पूरे समाज की सभ्यता का प्रश्न है। जिस समाज में नारी सुरक्षित, सम्मानित और आत्मनिर्भर होती है, वही समाज वास्तव में विकसित और मानवीय कहलाता है। इसलिए अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस का वास्तविक संदेश यही है कि नारी को सम्मान देने का कार्य केवल एक दिन का उत्सव नहीं, बल्कि पूरे वर्ष की सामाजिक चेतना होना चाहिए। जब समाज यह स्वीकार कर लेगा कि नारी केवल परिवार की आधारशिला नहीं, बल्कि भविष्य की निर्माता है, तब वह दिन दूर नहीं होगा जब 'नारी सशक्तिकरण' शब्द की आवश्यकता ही समाप्त हो जाएगी-क्योंकि नारी स्वाभाविक रूप से सशक्त होगी और तब शायद दुनिया सचमुच उस आदर्श को जी पाएगी, जिसे भारतीय संस्कृति ने हजारों वर्ष पहले कहा था- "यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता।"

प्रेरणा

सत्य का उजाला: एक बालक की ईमानदारी जिसने डाकुओं का रास्ता बदल दिया

मानव जीवन में सत्य की शक्ति इतनी गहरी और परिवर्तनकारी होती है कि वह सबसे कठोर हृदय को भी पिघला सकती है। इतिहास और लोककथाओं में कई ऐसे प्रसंग मिलते हैं, जहाँ एक छोटे से सत्य ने बड़ी क्रांति की शुरुआत की। यह कहानी भी एक ऐसे ही बालक की है, जिसकी सच्चाई ने न केवल उसकी महानता को उजागर किया बल्कि एक निर्दयी डाकू सरदार के जीवन की दिशा भी बदल दी। यह कथा हमें यह सिखाती है कि सत्य केवल एक नैतिक आदर्श नहीं, बल्कि वह शक्ति है जो अंधकार में भी प्रकाश का मार्ग दिखाती है।

बहुत समय पहले की बात है। एक लंबा काफिला विशाल रेगिस्तान से गुजर रहा था। वह यात्रा कठिन थी, क्योंकि चारों ओर फैली रेत, तपती धूप और दूर-दूर तक दिखाई देने वाली वीरानी यात्रियों को थका देती थी। फिर भी लोग अपने-अपने उद्देश्य लेकर उस मार्ग पर आगे बढ़ रहे थे। कुछ लोग व्यापार के लिए जा रहे थे, कुछ अपने परिवार से मिलने और कुछ जीवन की नई शुरुआत की तलाश में यात्रा कर रहे थे। उसी काफिले में एक बारह वर्ष का बालक भी शामिल था। वह उम्र में छोटा था, लेकिन उसके चेहरे पर गंभीरता और आत्मविश्वास झलकता था। उसके कपड़े साधारण थे और उसके पास कोई विशेष सामान भी नहीं था। वह शांत भाव से काफिले के साथ चल रहा था। दरअसल वह अपनी बीमार बहन की सेवा करने के लिए दूर एक शहर जा रहा था। जब वह घर से निकला था, तब उसकी मां ने उसे आशीर्वाद दिया था और जीवन की एक अमूल्य शिक्षा भी दी थी। मां ने अपने बेटे से कहा था, "बेटा, जीवन में चाहे कितनी भी कठिन परिस्थिति क्यों न आए, कभी झूठ मत बोलना। सत्य ही मनुष्य की सबसे बड़ी पूंजी है।" मां को यह भी चिंता थी कि रास्ता लंबा है और कहीं बेटे को पैसों की आवश्यकता पड़ सकती है। इसलिए उसने पांच सोने की अशर्फियां उसके लंगोट में छिपाकर रख दीं। जाते समय उसने बेटे से कहा, "इन अशर्फियों का उपयोग तभी करना जब बहुत जरूरी हो, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना—सत्य से कभी समझौता मत करना।" बालक ने अपनी मां की बात को दिल से स्वीकार किया और यात्रा पर निकल पड़ा। वह अपने मन में मां की सीख को दोहराता हुआ काफिले के साथ आगे बढ़ता रहा। कुछ दिन बाद जब काफिला रेगिस्तान के बीच पहुंचा, तो अचानक दूर से घोड़ों की तेज टापें सुनाई देने लगीं। यात्रियों ने घबराकर इधर-उधर देखा। कुछ ही क्षणों में हथियारों से लैस डाकुओं का एक गिरोह वहां आ पहुंचा और पूरे काफिले को चारों ओर से घेर लिया। यात्रियों के चेहरों पर भय साफ दिखाई देने लगा। किसी के पास बच निकलने का रास्ता नहीं था। डाकुओं ने बिना देर किए यात्रियों की तलाशी लेना शुरू कर दिया। वे एक-एक कर सभी से रुपये, गहने और कीमती सामान छीनने लगे। जो भी उनके हाथ लगता, वे उसे बेरहमी से अपने पास रख लेते। कुछ यात्रियों ने विरोध करने की कोशिश की, लेकिन हथियारबंद डाकुओं के सामने उनकी कोई नहीं चली। थोड़ी ही देर में काफिले के लगभग सभी लोग लूट लिए गए। उसी दौरान एक डाकू की नजर उस छोटे बालक पर पड़ी। उसने हंसते हुए कहा, "यह छोटा लड़का हमारे लिए क्या लाएगा?" फिर भी उसने उसकी तलाशी ली, लेकिन उसके पास से कोई सामान नहीं मिला। डाकू उसे अपने सरदार के पास ले गया और बोला, "सरदार, इसके पास कुछ भी नहीं है।" डाकुओं का सरदार अपने घोड़े पर बैठा सब कुछ देख रहा था। उसने बालक को ध्यान से देखा और हल्की मुस्कान के साथ पूछा, "बेटा, सच-सच बता, तेरे पास कुछ भी नहीं है? क्या तू गरीब है या अनाथ है?" बालक ने बिना किसी डर के शांत स्वर में उत्तर दिया, "मैं गरीब नहीं हूं। मेरी मां ने मेरे लंगोट में पांच सोने की अशर्फियां छिपाकर रखी हैं।" उसकी यह बात सुनकर वहां खड़े सभी डाकू चौंक गए। सरदार को भी विश्वास नहीं हुआ। उसने आश्चर्य से पूछा, "अगर तेरे पास सच में अशर्फियां हैं, तो तू हमें क्यों बता रहा है? क्या तुझे डर नहीं लगता कि हम उन्हें भी छीन लेंगे?" बालक ने पूरी सादगी से जवाब दिया, "मेरी मां ने मुझे दो बातें सिखाई हैं। पहली, कि इन अशर्फियों का उपयोग जरूरत पड़ने पर ही करना। और दूसरी, कि जीवन में कभी झूठ नहीं बोलना। आपने मुझसे पूछा कि मेरे पास कुछ है या नहीं, तो मैं झूठ कैसे बोल सकता था?" उसकी आवाज में इतनी सच्चाई और मासूमियत थी कि कुछ क्षणों के लिए वहां सन्नाटा छा गया। डाकू सरदार उस बालक को देखते रह गया। उसके मन में एक अजीब-सी हलचल होने लगी। उसने अपने जीवन में पहली बार इतनी निष्कपट ईमानदारी देखी थी। सरदार धीरे-धीरे घोड़े से नीचे उतरा और बालक के पास आकर खड़ा हो गया। उसकी आंखों में भावुकता झलक रही थी। उसने कहा, "बेटा, तू इतना छोटा है, फिर भी अपनी मां की बात का इतना सम्मान करता है। और मैं मैं वर्षों से लोगों को लूटता रहा हूं, निर्दोष यात्रियों को दुख देता रहा हूं।" सरदार की आवाज भर्रा गई। उसने अपने साथियों की ओर देखा और कहा, "यह बच्चा हमें सच बता रहा है, जबकि हम इसे लूटने आए हैं। अगर यह अपनी मां की सीख के प्रति इतना ईमानदार हो सकता है, तो क्या हम अपने जीवन को नहीं बदल सकते?" उसके शब्द सुनकर बाकी डाकू भी चुप हो गए। सरदार के भीतर जैसे कोई नई चेतना जाग उठी थी। उसने तुरंत आदेश दिया कि सभी यात्रियों से लूटा हुआ सामान वापस कर दिया जाए। डाकुओं ने पहले तो आश्चर्य से उसकी ओर देखा, लेकिन सरदार का आदेश मानना ही पड़ा। कुछ ही देर में यात्रियों का सारा सामान उन्हें वापस मिल गया। जो लोग थोड़ी देर पहले भय और निराशा से घिरे थे, उनके चेहरे पर अब राहत और आश्चर्य के भाव थे। सरदार ने बालक के सिर पर हाथ रखते हुए कहा, "बेटा, आज तूने मुझे सिखाया है कि सच्चाई कितनी शक्तिशाली होती है। मैं आज से वचन देता हूं कि कभी लूटपाट नहीं करूंगा और ईमानदारी का रास्ता अपनाऊंगा।" उस दिन के बाद डाकू सरदार का जीवन सचमुच बदल गया। उसने अपराध का मार्ग छोड़ दिया और एक सम्मानजनक जीवन जीने लगा। लोगों के बीच उसका व्यवहार भी बदल गया और वह दूसरों की मदद करने लगा। वह बालक भी आगे चलकर अपने सत्य और नैतिकता के कारण प्रसिद्ध हुआ। उसकी ईमानदारी और धर्मपरायणता के कारण लोग उसे "खलीफा अमीन" के नाम से जानने लगे। उसकी कहानी पीढ़ियों तक लोगों को प्रेरित करती रही कि सच्चाई कभी व्यर्थ नहीं जाती। यह घटना हमें यह सिखाती है कि सत्य का प्रभाव केवल व्यक्तिगत जीवन तक सीमित नहीं रहता। एक व्यक्ति की ईमानदारी पूरे समाज को प्रभावित कर सकती है।

महिलाओं के योगदान को मिलती पहचान, गरिमापूर्ण रोजगार के नए अवसर हो रहे सृजित

देश आठ मार्च को अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस मनाने की तैयारी कर रहा है। भारत की विकास यात्रा में महिलाओं की भूमिका परिधि में नहीं, बल्कि केंद्र में रही है। आज समाज की हर दृश्यमान उपलब्धि के पीछे महिला संचालित एक आधारशक्ति अनवरत कार्य कर रही है, जिसका नाम है-देखभाल की अर्थव्यवस्था यानी केयर इकोनमी। यह वह मौन ऊर्जा है, जो भारत के अस्तित्व को हर पल संबल प्रदान करती है।

यह उस मां का समर्पण है, जो सूर्योदय से पूर्व अपनों के लिए भोजन पकाती है और फिर जीविका की चुनौतियों की ओर निकल पड़ती है। यह उस पत्नी की अटूट निष्ठा है, जो कठिन से कठिन समय में भी परिवार की नींव को दरकने नहीं देती। यह उस बेटी का निःस्वार्थ भाव है, जो दिन भर की थकान के बाद भी रात के पहर अपने माता-पिता के सिरहाने बैठती है। यह शक्ति किसी यश या प्रशंसा की आकांक्षी नहीं है। वह तो बस कर्तव्य की उस अविरल धारा की तरह है, जो बिना शोर मचाए सृजन करती रहती है।

ऐतिहासिक रूप से महिलाओं के योगदान का एक विशाल हिस्सा विशेषकर अवैतनिक देखभाल, अनौपचारिक श्रम और सामुदायिक सेवा पारंपरिक आर्थिक गणनाओं की परिधि से बाहर रहा है। इसे देखते हुए मोदी सरकार ने देखभाल के इस अदृश्य पहलू को कम करने, उसे सामाजिक मान्यता देने और उसके न्यायसंगत पुनर्वितरण पर बल दिया है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में महिलाओं को केवल लाभार्थी के रूप में नहीं, बल्कि विकास के अग्रदूत के रूप में मान्यता दी गई है। महिला नेतृत्व वाला विकास आज एक सशक्त नीतिगत दृष्टि है, जो बजट, कार्यक्रमों और संस्थागत सुधारों में परिलक्षित होती है। सरकार का दृष्टिकोण देखभाल से जुड़ी सेवाओं को पेशेवर स्वरूप प्रदान कर उन्हें समावेशी विकास के एक नए इंजन के रूप में रूपांतरित करना है। यही कारण है कि हाल में भारत में महिला श्रम शक्ति सहभागिता दर में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जो 2017-18 में 23.3 प्रतिशत से बढ़कर 2023-24 में 41.7 प्रतिशत हो गई है। यह आंकड़ा भारतीय महिलाओं की बढ़ती आकांक्षाओं और आर्थिक गतिविधियों में उनके बढ़ते प्रभुत्व का सूचक है। सवैतनिक कार्यों में महिलाओं की यह भागीदारी न केवल घरेलू समृद्धि का आधार बन रही है, बल्कि राष्ट्रीय उत्पादकता को भी नई ऊंचाइयों पर ले जा रही है। आर्थिक सर्वेक्षण इस वास्तविकता को रेखांकित करता है कि यदि हम अवैतनिक देखभाल के बोझ को कम कर सकें और इन सेवाओं को एक व्यावसायिक स्वरूप प्रदान करें तो महिला रोजगार के परिदृश्य में एक क्रांतिकारी बदलाव आएगा। भारतीय केयर इकोनमी वर्तमान में लाखों लोगों की आजीविका का संबल है और आने वाले दशक में इसमें रोजगार सृजन की अपार संभावनाएं हैं। यही कारण है कि केंद्रीय बजट 2026-27 में केयर इकोनमी को सुदृढ़ करने पर विशेष बल दिया गया है।

महिलाओं के नेतृत्व में विकास के प्रति सरकार की अटूट प्रतिबद्धता ऐतिहासिक जेंडर बजट में स्पष्ट झलकती है, जिसका आवंटन अब तक के उच्चतम स्तर पांच लाख करोड़ रुपये से अधिक पर पहुंच गया है। मोदी सरकार 1.5 लाख देखभालकर्ताओं के कौशल विकास में भी निवेश कर रही है, कामकाजी महिला छात्रावासों का विस्तार कर रही है और आंगनबाड़ी केंद्रों को आधुनिक बनाकर प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल सुनिश्चित कर रही है। इसके साथ ही स्वास्थ्य एवं पोषण प्रणालियों के समन्वय को भी सशक्त किया जा रहा है। ये सभी प्रयास एक स्पष्ट राजनीतिक और नैतिक प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं कि जब महिलाओं को आवश्यक सहयोग और मंच मिलता है तो संपूर्ण अर्थव्यवस्था की गति तीव्र हो जाती है। सामाजिक सुरक्षा संहिता और व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कार्य स्थिति संहिता जैसे वैधानिक ढांचे शिशु देखभाल केंद्रों और श्रमिक कल्याण के प्रविधानों को सुदृढ़ करते हैं। ये सुधार एक गहरे सिद्धांत को प्रतिपादित करते हैं कि शिशु देखभाल सहायता कोई सुविधा मात्र नहीं, बल्कि आर्थिक न्याय का एक अनिवार्य संरचनात्मक आधार है। मोदी सरकार महिलाओं और बच्चों को राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के केंद्र में रखती है, जो देश की कुल जनसंख्या का 65 प्रतिशत से अधिक हिस्सा हैं। उनका सर्वांगीण कल्याण एक अनिवार्य रणनीतिक आवश्यकता है। 2050 तक वरिष्ठ नागरिकों की संख्या में बढ़ोतरी होगी। इससे परिवार के भीतर भी देखभाल से जुड़ी जिम्मेदारियां बढ़ेंगी। साथ ही करोड़ों बच्चों को व्यवस्थित प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा, सुदृढ़ पोषण और स्वास्थ्य सहायता की नितांत आवश्यकता होगी। आज तेजी से होते शहरीकरण, प्रवासन और एकल परिवारों के बढ़ते चलन ने हमारी पारंपरिक सामाजिक सहायता प्रणालियों को बदल दिया है। अनौपचारिक ढांचों पर बढ़ते दबाव के कारण अब सुलभ, किफायती और गुणवत्तापूर्ण शिशु देखभाल एवं पारिवारिक सेवाओं की आवश्यकता अनिवार्य होती जा रही है। संगठित और सामुदायिक सेवाओं की यह मांग केवल महानगरों तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि द्वितीय एवं तृतीय श्रेणी के शहरों और ग्रामीण जनपदों में भी तीव्रता से उभरेगी। देखभाल की अर्थव्यवस्था में निवेश एक साथ कई राष्ट्रीय लक्ष्यों को मजबूत करता है। इससे महिला श्रमशक्ति की भागीदारी बढ़ती है, बाल विकास के परिणाम सुधरते हैं, बुजुर्गों का कल्याण सुनिश्चित होता है और गरिमापूर्ण रोजगार के नए अवसर सृजित होते हैं। देखभाल प्रणालियों के संस्थागत और पेशेवर होने से महिलाएं सशक्त होती हैं, परिवारों को स्थिरता मिलती है और संपूर्ण अर्थव्यवस्था को गति प्राप्त होती है।

अभियान

हिमालय की नीरव गोद में केदारताल: शिवत्व, प्रकृति और आत्मशांति का दिव्य संगम

हिमालय केवल पर्वतों की श्रृंखला नहीं है, वह भारतीय चेतना, अध्यात्म और प्रकृति के विराट संतुलन का प्रतीक है। इसकी ऊँचाइयों में अनगिनत ऐसे स्थल छिपे हुए हैं, जहाँ प्रकृति की नीरवता स्वयं एक आध्यात्मिक संवाद बन जाती है। यहाँ जब मनुष्य पहुँचता है तो उसे केवल दृश्य सौंदर्य ही नहीं मिलता, बल्कि वह अपने भीतर भी एक गहरी शांति का अनुभव करता है। इसी दिव्य और रहस्यमय हिमालयी क्षेत्र में एक अद्भुत झील स्थित है, जिसे केदारताल कहा जाता है। यह झील उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में लगभग साढ़े चार हजार मीटर की ऊँचाई पर स्थित है और अपनी अद्भुत प्राकृतिक सुंदरता तथा धार्मिक महत्व के कारण साधकों, पर्वतारोहियों और प्रकृति प्रेमियों के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र बनी हुई है।

केदारताल का नाम लेते ही मन में हिमालय की एक ऐसी छवि उभरती है, जहाँ चारों ओर बर्फ से ढकी चोटियाँ, नीले आकाश का विस्तार और बीच में शांत, गहरी झील का जल दिखाई देता है। यह झील थलय सागर, मेरु और भृगुपंथ जैसी प्रसिद्ध पर्वत चोटियों के हिम से निर्मित होती है। इन ऊँचे शिखरों से पिघलने वाला हिम धीरे-धीरे इस झील में एकत्रित होता है और यहीं से केदार गंगा का उद्गम माना जाता है। यही पवित्र धारा आगे चलकर भागीरथी नदी से मिलती है, जो गंगा के महान प्रवाह का हिस्सा बन जाती है। इस प्रकार केदारताल केवल एक प्राकृतिक जलाशय नहीं है, बल्कि वह गंगा की पवित्र धारा से भी जुड़ा हुआ एक आध्यात्मिक स्रोत है।

भारतीय परंपरा में जल को जीवन और पवित्रता का प्रतीक माना गया है। जब यह जल हिमालय की गोद में स्थित किसी पवित्र स्थल से उत्पन्न होता है, तो उसका महत्व और भी बढ़ जाता है। केदारताल की यही विशेषता इसे एक साधारण झील से अलग बनाती है। यहाँ पहुँचने वाला व्यक्ति केवल प्रकृति की सुंदरता नहीं देखता, बल्कि उसे ऐसा अनुभव होता है जैसे वह किसी प्राचीन आध्यात्मिक ऊर्जा के क्षेत्र में प्रवेश कर रहा हो।

केदारताल के साथ एक अत्यंत रोचक पौराणिक कथा भी जुड़ी हुई है। यह कथा उस समय की है जब देवताओं और असुरों ने मिलकर समुद्र मंथन किया था। इस मंथन का उद्देश्य अमृत प्राप्त करना था, जिससे देवताओं को अमरता मिल सके। किंतु जब समुद्र का मंथन आरंभ हुआ तो अमृत से पहले एक भयानक विष प्रकट हुआ, जिसे कालकूट विष कहा गया। यह विष इतना प्रचंड और घातक था कि उसके प्रभाव से संपूर्ण सृष्टि के विनाश का खतरा उत्पन्न हो गया। देवता और असुर दोनों ही इस विष को देखकर भयभीत हो गए और किसी को भी यह समझ नहीं आ रहा था कि इस संकट से संसार को कैसे बचाया जाए। ऐसे समय में भगवान शिव ने संपूर्ण सृष्टि की रक्षा के लिए उस विष को अपने कंठ में धारण कर लिया। यह विष इतना प्रबल था कि उसे पीने के बाद उनका कंठ नीला पड़ गया और तभी से वे नीलकंठ के नाम से प्रसिद्ध हुए। यह घटना केवल एक पौराणिक प्रसंग नहीं है, बल्कि वह त्याग, करुणा और संतुलन का प्रतीक भी है। शिव ने यह दिखाया कि सच्चा नेतृत्व वही है जो दूसरों की रक्षा के लिए स्वयं कष्ट सहने को तैयार हो।

लोक मान्यताओं के अनुसार, कालकूट विष की तीव्रता को शांत करने के लिए भगवान शिव ने हिमालय के इसी क्षेत्र में स्थित केदारताल के पवित्र जल का सेवन किया था। इसीलिए इस झील को शिव का ताल या शिव ताल भी कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस झील के जल में एक अद्भुत आध्यात्मिक ऊर्जा विद्यमान है, जो शिव की तपस्या और करुणा की स्मृति को आज भी जीवित रखती है।

जब कोई व्यक्ति इस स्थान पर पहुँचता है, तो उसे हिमालय की नीरवता में एक अलग ही प्रकार की अनुभूति होती है। चारों ओर फैली बर्फ, दूर तक फैली पर्वत श्रृंखलाएँ और बीच में शांत झील का स्थिर जल ऐसा प्रतीत कराता है मानो समय यहाँ ठहर गया हो। प्रकृति यहाँ किसी शब्द के बिना ही अपना संदेश देती है। यहाँ का मौन भी बोलता हुआ प्रतीत होता है।

केदारताल तक पहुँचने का मार्ग आसान नहीं है। यह यात्रा साहस, धैर्य और शारीरिक क्षमता की परीक्षा लेती है। इस पवित्र झील तक पहुँचने के लिए यात्रियों को गंगोत्री से लगभग बीस किलोमीटर लंबा कठिन ट्रेक करना पड़ता है। यह मार्ग ऊबड़-खाबड़ पहाड़ी रास्तों, खड़ी चढ़ाइयों और बर्फ से ढके क्षेत्रों से होकर गुजरता है। गंगोत्री से शुरू होने वाला यह ट्रेक सामान्यतः तीन से चार दिनों में पूरा किया जाता है।

गंगोत्री स्वयं एक अत्यंत पवित्र स्थान है, जहाँ से गंगा के उद्गम की यात्रा आरंभ होती है। यह स्थल समुद्र तल से लगभग 3100 मीटर की ऊँचाई पर स्थित है और यहाँ तक पहुँचने के लिए देहरादून या ऋषिकेश से सड़क मार्ग द्वारा यात्रा की जाती है। देहरादून से गंगोत्री की दूरी लगभग 270 किलोमीटर है और इस मार्ग को तय करने में सात से आठ घंटे का समय लगता है। जैसे-जैसे यात्री गंगोत्री से आगे बढ़ता है, प्रकृति का स्वरूप और भी अधिक कठोर तथा भव्य होता जाता है।

केदारताल की यात्रा केवल एक साहसिक ट्रेक नहीं है, बल्कि वह आत्मिक अनुभव भी है। रास्ते में मिलने वाली ठंडी हवाएँ, ऊँचे पर्वतों की छाया और दूर तक फैले हिमखंड यात्रियों को यह एहसास कराते हैं कि मनुष्य प्रकृति के सामने कितना छोटा है। इस यात्रा के दौरान व्यक्ति अपने भीतर के भय, थकान और सीमाओं से भी परिचित होता है। जब अंततः वह केदारताल के शांत जल के सामने खड़ा होता है, तो उसे एक गहरी संतुष्टि और आत्मिक शांति का अनुभव होता है।

आज के समय में जब मानव सभ्यता विज्ञान, तकनीक और भौतिक सुविधाओं के शिखर पर पहुँच चुकी है, तब भी मनुष्य के भीतर एक प्रकार की बेचैनी और असंतुलन दिखाई देता है। आधुनिक जीवन की तेज गति, भोग-विलास की अंधी दौड़ और प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन पर्यावरण और मानसिक स्वास्थ्य दोनों के लिए संकट बनता जा रहा है। ऐसे समय में केदारताल जैसे स्थान हमें यह याद दिलाते हैं कि प्रकृति केवल संसाधन नहीं है, बल्कि वह जीवन का आधार और संतुलन का स्रोत है।

हिमालय की इन ऊँचाइयों में स्थित यह झील हमें एक गहरा दार्शनिक संदेश भी देती है। भगवान शिव द्वारा विष को धारण करने की कथा केवल धार्मिक आस्था का विषय नहीं है, बल्कि वह जीवन के एक महत्वपूर्ण सिद्धांत की ओर संकेत करती है। यह सिद्धांत है संतुलन और जिम्मेदारी का। जिस प्रकार शिव ने विष को पीकर संसार को बचाया, उसी प्रकार आज मानव समाज को भी उस विष को पहचानना होगा जिसे उसने स्वयं अपनी सृष्टि में घोल दिया है।

आज प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन और पर्यावरणीय संकट उसी विष के रूप में हमारे सामने खड़े हैं। यदि मनुष्य ने अपने व्यवहार में संयम, करुणा और जिम्मेदारी नहीं दिखाई, तो यह विष धीरे-धीरे संपूर्ण पृथ्वी को प्रभावित कर सकता है। केदारताल की कथा हमें यह सिखाती है कि प्रकृति के साथ संतुलन बनाए रखना केवल एक विकल्प नहीं बल्कि एक अनिवार्यता है।

इस झील के शांत जल में झलकती हिमालय की छाया मानो यह संदेश देती है कि वास्तविक शांति बाहरी उपलब्धियों से नहीं, बल्कि भीतर के संतुलन और संयम से प्राप्त होती है। जब मनुष्य प्रकृति के साथ सामंजस्य स्थापित करता है, तभी वह अपने जीवन में सच्चे अर्थों में संतुलन और आनंद का अनुभव कर सकता है।

केदारताल का यह दिव्य स्थल आज भी उन लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बना हुआ है, जो जीवन के गहरे अर्थों को समझना चाहते हैं। यहाँ की नीरवता, यहाँ का सौंदर्य और यहाँ से जुड़ी पौराणिक कथाएँ हमें यह याद दिलाती हैं कि प्रकृति और अध्यात्म के बीच का संबंध बहुत गहरा और प्राचीन है। हिमालय की गोद में स्थित यह पवित्र झील केवल एक पर्यटन स्थल नहीं है, बल्कि वह मानव चेतना को जागृत करने वाला एक जीवंत प्रतीक है, जो हमें सिखाती है कि जीवन का वास्तविक संतुलन बाहरी संसार में नहीं, बल्कि हमारे भीतर छिपा हुआ है।

RNI No. GUJHIN/2011/39228 Printed, Published & Owned by AJAYKUMAR RAMANLAL PRAJAPATI and Printed By (1) JIGNESH RASHIKBHAI GAJJAR at Vansh Corporation, A/8, Shayona Golden Estate, Shahibag, Ahmedabad - 380 004
(2) DESAI RAHUL MAHESHBHAI at Bhavani Offset, "Bhatiya Ni Wadi, Opp Kalupur Railway Station, Kalupur, Ahmedabad-380 002. (3) HADIK MAHESHBHAI DESAI at Bhoomi Offset, "Bhatiya Ni Wadi, Opp Kalupur Railway Station, Kalupur, Ahmedabad-380 002
and Published from TF-01, Nanakram Super Market, Ramnagar, Sabarmati, Ahmedabad - 380 005. Editor : MANOJKUMAR CHAMPAKLAL SHAH
Rage.Office: TF-01, Nanakram Super Market, Ramnagar, Sabarmati, Ahmedabad - 380 005 Gujarat,India. Phone : (O) 9016333307(M)9328333307,9825333307
Email : garvigujarat2007@gmail.com*garvigujarat2007@yahoo.com*Website : www.garvigujarat.co.in

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल के 500 एकड़ से अधिक जमीन को लिफ्ट इरिगेशन की सुविधा का लाभ

- मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने जिले के उमरपाडा-नर्मदा की डेडियापाडा तहसील के आदिजाति किसानों के खेतों तक पानी पहुंचाने वाली उकाई जलाशय आधारित तापी-करजण लिंक पाइपलाइन उद्वहन सिंचाई योजना का लोकार्पण किया
- उमरपाडा के 29 गांवों की 19,150 एकड़ भूमि को सिंचाई सुविधा देने के लिए 210 करोड़ रुपए की लागत से होने वाली योजना के एक्सटेंशन का भूमिपूजन सम्पन्न हुआ
- प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के विकसित भारत @2047 के संकल्प में विकसित गुजरात के निर्माण से लीड लेने के लिए आदिवासी क्षेत्रों को मुख्यमंत्री का प्रेरक आह्वान
- राज्य सरकार 'नल से जल' से लेकर 'खेत तक जल' पहुंचाने के लिए निरंतर कार्यशील है : आदिजाति विकास मंत्री श्री नरेशभाई पटेल
- राज्य में 14,756 छोटे चेकडैम बनाकर 1.52 लाख एकड़ भूमि को सिंचाई का लाभ दिया गया है : जल संसाधन एवं जल आपूर्ति राज्य मंत्री ईश्वरसिंह पटेल
- सूरत शहर-जिले में 126 करोड़ रुपए के विभिन्न विकास कार्यों का ई-लोकार्पण और शिलान्यास

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल

- प्रधानमंत्री ने आदिजाति क्षेत्रों के सर्वांगीण विकास के लिए 2 लाख करोड़ रुपए की जनजातीय कल्याण योजना की भेंट दी है
- आगामी पांच वर्षों में अंबाजी से उमरगाम तक के आदिजाति बेल्ट में शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सड़क इन्फ्रास्ट्रक्चर के कार्यों को गति मिलेगी
- सुदूरवर्ती तथा जनसामान्य के विकास को कल्याण योजनाओं के केंद्र में रखकर विकास की राजनीति का युग गुजरात में प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में साकार हुआ है

(जीएनएस)। गांधीनगर, : मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने विकसित भारत @2047 के प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के संकल्प को साकार करने के लिए विकसित गुजरात के निर्माण में आदिजाति क्षेत्रों को विकास की लीड लेने का प्रेरक आह्वान किया। मुख्यमंत्री ने शनिवार को दक्षिण गुजरात के सूरत जिले के आदिवासी क्षेत्र उमरपाडा और नर्मदा जिले की डेडियापाडा तहसील के 73 आदिवासी गांवों की 53,750 एकड़ भूमि को सिंचाई सुविधा प्रदान करने वाली तापी-करजण लिंक पाइपलाइन उद्वहन सिंचाई योजना के लोकार्पण अवसर पर प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के संकल्प को साकार करने का आह्वान किया। उकाई जलाशय योजना आधारित इस उद्वहन सिंचाई योजना का निर्माण 651.08 करोड़ रुपए की लागत से हुआ है। इसके लोकार्पण के साथ मुख्यमंत्री ने 208.51 करोड़ रुपए की लागत से होने वाले इस योजना के एक्सटेंशन कार्य का भी ई-तकती अनावरण के माध्यम से भूमिपूजन किया। इस एक्सटेंशन योजना के पूर्ण होने से उमरपाडा तहसील के 29 गांवों की 19,141 एकड़ भूमि को सिंचाई का लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने वित्त मंत्री श्री कनुभाई देसाई, आदिजाति विकास मंत्री श्री नरेशभाई पटेल, जल आपूर्ति राज्य मंत्री श्री ईश्वरसिंह पटेल तथा सांसदों की उपस्थिति में सूरत जिले में 126 करोड़ रुपए के लगभग 12 विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। उन्होंने वन अधिकार नियम के तहत आदिजाति लाभार्थियों को प्रमाण पत्र वितरण, पीएमएवाई आवास, गोदाम सहायता और ट्रैक्टर सहायता का वितरण किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि जनसामान्य एवं सुदुरवर्ती व्यक्ति को विकास की मुख्यधारा में लाने के लिए विकास की राजनीति का युग प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में शुरू हुआ है। विकास की प्रत्येक योजना के केंद्र में उन्होंने जनसामान्य के हितों को प्राथमिकता दी है।

श्री पटेल ने कहा कि सूरत जिले के उमरपाडा तथा नर्मदा के डेडियापाडा गांवों में उकाई जलाशय योजना आधारित इस उद्वहन सिंचाई योजना में लगभग 87 मंजिल जितनी ऊंचाई तक पाइपलाइन द्वारा पानी उठाकर आदिवासी क्षेत्रों को सिंचाई के लिए उपलब्ध कराने की इंजीनियरिंग कुशलता भी प्रधानमंत्री के विजनरी लीडरशिप से संभव हुई है। मुख्यमंत्री ने उल्लेख किया कि अंबाजी से उमरगाम तक पूरे आदिवासी बेल्ट में शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क-इन्फ्रास्ट्रक्चर, आवास, बिजली और पानी जैसी सुविधाएं पहुंचाने के लिए प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गई वनबंधु कल्याण योजना अत्यंत उपकारी सिद्ध हुई है।

मुख्यमंत्री ने जोड़ा कि इतना ही नहीं; प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने हाल ही में भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के अवसर पर जनजातीय गौरव दिवस पर गुजरात के आदिवासी क्षेत्रों के सर्वांगीण विकास के लिए पांच वर्षों में 2 लाख करोड़ रुपए की 'जनजातीय कल्याण योजना' की घोषणा की है। वार्षिक 35,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था से शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क और इन्फ्रास्ट्रक्चर कार्यों को अधिक गति मिलेगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री के विकासवादी दृष्टिकोण से आदिवासी क्षेत्रों में विकास और समृद्धि के नए द्वार खुले हैं। आज आदिवासी क्षेत्रों में साइंस स्कूल-कॉलेज और मेडिकल कॉलेज शुरू होने से आदिवासी बेटे एवं बेटियां इंजीनियर और डॉक्टर बन रहे हैं। पायलट बनने के लिए भी सरकार 25 लाख रुपए तक की लोन सहायता दे रही है, जिसका लाभ लेकर आदिवासी युवाएं आसमान छू रहे हैं।

उन्होंने आगे कहा कि 'विकास भी, विरासत भी' के लक्ष्य के साथ विकास कार्यों के साथ-साथ देश के इतिहास और संस्कृति को उजागर करने का महत्वपूर्ण कार्य प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कर रहे हैं। यह कहकर मुख्यमंत्री ने राम मंदिर के निर्माण से लेकर पावागढ के शिखर पर ध्वजारोहण तक सांस्कृतिक पुनर्जागरण की भूमिका प्रदान की।

मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन की शुरुआत राज्य के पूर्व मंत्री और उमरेठ के विधायक स्वर्गीय गोविंदभाई परमार को श्रद्धांजलि प्रदान कर की।

इस अवसर पर आदिजाति विकास मंत्री श्री नरेशभाई पटेल ने कहा कि, राज्य सरकार ने दुर्गम क्षेत्रों में भी सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने का बीड़ा उठाया है। हमारी सरकार 'नल से जल' से लेकर 'खेत तक जल' पहुंचाने के लिए कटिबद्ध है। अतीत में जिन क्षेत्रों को नसीब के भरोसे छोड़ दिया गया था, वहां आज इंजीनियरिंग कौशल से हम लिफ्ट इरिगेशन के माध्यम से पानी का उद्वहन करके पहुंचा रहे हैं। जब किसान के खेत में बारहों महीने पानी होगा, तभी वह समृद्ध होगा और उसका लाभ राज्य की अर्थव्यवस्था को होगा।

आदिजाति विकास मंत्री ने आगे कहा कि देवमोगरा और शबरीधाम जैसे धार्मिक स्थलों के विकास के लिए भी सरकार प्रतिबद्ध है। आदिवासी समाज की बेटियां अब उच्च शिक्षा प्राप्त कर रही हैं। भगवान बिरसा मुंडा के नाम पर प्रत्येक तहसील में लाइब्रेरी स्थापित करने की दिशा में सरकार कार्य कर रही है।

जल संसाधन एवं जल आपूर्ति राज्य मंत्री श्री ईश्वरसिंह पटेल ने कहा कि उमरपाडा तथा डेडियापाडा तहसील के गांव ऊंचाई पर होने के कारण दोगुना वर्षा होने के बावजूद भी रबी और गर्मी की फसल लेने के लिए पानी के बिना किसान तरसते थे। परिश्रम और ठोस योजना के साथ पानी को लिफ्ट करके इन क्षेत्रों की वर्षों पुरानी सिंचाई समस्या का समाधान किया गया है।

मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने 14,756 छोटे चेकडैम बनाकर 1.52 लाख एकड़ भूमि को सिंचाई का लाभ दिया है। जबकि 735 बड़े चेकडैम के माध्यम से 80,500 एकड़ क्षेत्र में पानी पहुंचाया गया है। 3500 तालाबों को गहरा करके किसानों को पानी मिलता रहे, इसके लिए व्यवस्था की गई है। श्री पटेल ने आगे कहा कि सोनगढ, उच्छल, निझर और कुकुरमुंडा तहसील के दूरदराज क्षेत्रों के लिए 912 करोड़ रुपए की उद्वहन पाइपलाइन योजना का कार्य प्रगति में है। इस योजना के लाभ से अनुमानित 69 हजार एकड़ क्षेत्र और 14,117 परिवारों को प्रत्यक्ष लाभ मिलेगा। दक्षिण गुजरात में अधिक वर्षा होने के बावजूद जनवरी महीने से पानी की कमी महसूस होती है, ऐसे में इस समस्या के समाधान के लिए विभिन्न नदियों पर इस वर्ष 522 करोड़ रुपए की लागत से अनुमानित 249 चेकडैम और वीयर (मेड़) बनाने की योजना है, जिससे 16,990 एकड़ क्षेत्र को प्रत्यक्ष या परोक्ष लाभ मिलेगा।

सांसद श्री प्रभुभाई वसावा ने कहा कि राज्य सरकार हमेशा आदिजाति नागरिकों और किसानों के लिए सकारात्मक रही है। आदिवासी किसानों को पर्याप्त मात्रा में सिंचाई सुविधा मिलने से वर्ष में अनेक प्रकार की फसलें, सब्जियां और फल-फूल का उत्पादन संभव होगा। परिणामस्वरूप किसानों के सर्वांगीण विकास का मार्ग प्रशस्त होगा। उद्वहन सिंचाई योजनाओं के माध्यम से गांव-गांव सिंचाई की जल सुविधा उपलब्ध होने से किसानों की समृद्धि के द्वार खुलेंगे।

सांसद श्री मनसुखभाई वसावा ने प्रसंगिक उद्बोधन करते हुए सिंचाई योजना के भगीरथ कार्य के लिए राज्य सरकार को बधाई दी।

विधायक श्री गणपतसिंह वसावा ने कहा कि तापी-करजण लिंक पाइपलाइन सिंचाई योजना साकार होने से उमरपाडा और डेडियापाडा तहसील के आदिवासी परिवारों के आंगन में सोने का सूरज उगा है। इस योजना के माध्यम से पहाड़ी और जंगल क्षेत्र के सुदूरवर्ती क्षेत्रों तक सिंचाई का पानी पहुंचने से यह पूरा क्षेत्र नंदन वन बन जाएगा और पर्यावरण तथा संस्कृति का संरक्षण करते हुए आदिवासी किसानों की खेती का कायाकल्प होगा।

उन्होंने आगे कहा कि राज्य सरकार गरीबों और आदिवासियों के सर्वांगीण विकास के लिए संकल्पबद्ध है। पहाड़ी और दुर्गम जंगल क्षेत्रों में लगभग 17 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन बिछाकर खेती के लिए पानी उपलब्ध कराया गया है, जो किसानों की आर्थिक समृद्धि में बड़ा योगदान देगा। इस अवसर पर उन्होंने शिक्षा क्षेत्र में सरकार की प्रतिबद्धता दोहराते हुए कहा कि, उमरपाडा तहसील में साइंस कॉलेज के आधुनिक भवन के निर्माण के लिए 27 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई है।

इस अवसर पर विधायक सर्वश्री कुंवरजीभाई हळपति, मोहनभाई ढोडिया, दर्शनाबेन देशमुख, मोहनभाई कोंकणी, संदीपभाई देसाई, जिला पंचायत की अध्यक्ष श्रीमती भाविनीबेन पटेल, जलआपूर्ति विभाग के सचिव श्री पी.सी. व्यास, सूरत जिला कलेक्टर डॉ. सौरभ पारधी, नर्मदा-सूरत जिला कलेक्टर श्री एस.के. मोदी, अग्रणी श्री भरत राठोड, श्री नील राव सहित सिंचाई विभाग के अधिकारी, आदिजाति किसान और ग्रामीण उपस्थित रहे।

एमसीएक्स-आईपीएफ कॉमक्वेस्ट 2026 प्रतियोगिता की 8वीं संस्करण सफलतापूर्वक सम्पन्न

(जीएनएस)। भारत भर की 1000 से अधिक शैक्षणिक संस्थाओं के छात्रों ने भाग लिया मुंबईः कमोडिटी बाजारों पर छात्रों के लिए राष्ट्रीय स्तर की प्रमुख शैक्षणिक क्विज एमसीएक्स-आईपीएफ कॉमक्वेस्ट 2026 की 8वीं संस्करण 27 फरवरी 2026 को भव्य फाइनल के साथ सफलतापूर्वक समाप्त हो गई। एमसीएक्स इंवेस्टर प्रोटेक्शन फंड (एमसीएक्स-आईपीएफ) द्वारा आयोजित इस प्रतियोगिता में 12,000 से अधिक छात्रों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया, जिसमें भारत के 30 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 1000 से अधिक शैक्षणिक संस्थाओं से 300 से अधिक शहरों में पंजीकरण हुआ था।

इस वर्ष के संस्करण में विभिन्न प्रबंधन संस्थानों, विश्वविद्यालयों और कॉलेजों के छात्रों ने भाग लिया, जो कमोडिटी डेरिवेटिव्स बाजारों और भारत की वित्तीय इकोसिस्टम में उनकी भूमिका को समझने के लिए छात्रों में बढ़ते रुचि को दर्शाता है।

प्रतिभागियों का मूल्यांकन कमोडिटी बाजारों के ज्ञान और विश्लेषणात्मक समझ के आधार पर तीन महीने तक चलने वाली बहु-चरणीय प्रतियोगिता के माध्यम से सावधानीपूर्वक किया गया। चयन प्रक्रिया में स्क्रीनिंग राउंड, केस-आधारित मूल्यांकन और इंटरएक्टिव मूल्यांकन प्रारूप शामिल थे, जो विचार की स्पष्टता, बाजार जागरूकता और अनुप्रयोग कौशलों की जांच के लिए डिज़ाइन किए गए थे।

ज़ोनल राउंड प्रमुख शैक्षणिक केंद्रों में आयोजित किए गए, जिनका समापन मुंबई विश्वविद्यालय, मुंबई स्थित ग्रीन टेक्नोलॉजी ऑडिटोरियम में भव्य फाइनल के साथ हुआ। फाइनल में देश भर की शीर्ष टीमें एकत्र हुईं, जिन्होंने असाधारण ज्ञान की गहराई और प्रतिस्पर्धी उत्कृष्टता प्रदर्शित की।

2019 में शुरू की गई एमसीएक्स-आईपीएफ कॉमक्वेस्ट एमसीएक्स इंवेस्टर प्रोटेक्शन फंड (एमसीएक्स-आईपीएफ) की प्रमुख वित्तीय साक्षरता पहल है। यह प्रतियोगिता एमसीएक्स-आईपीएफ के निरंतर निवेशक जागरूकता और शिक्षा प्रयासों का अभिन्न अंग है, जिसका उद्देश्य युवाओं में कमोडिटी डेरिवेटिव्स बाजारों की समझ बढ़ाना है। वर्षों से कॉमक्वेस्ट एक विश्वसनीय राष्ट्रीय मंच के रूप में विकसित हुआ है, जो शिक्षा जगत और कमोडिटी बाजार व्यवस्था (एक्सचेंज, क्लियरिंग निगम और बाजार मध्यस्थों सहित) के बीच सार्थक जुड़ाव को प्रोत्साहित करता है।

श्रीमती प्रवीणा राय, प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी, एमसीएक्स ने कहाः "आज कमोडिटी बाजार वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला, मैक्रोइकॉनॉमिक परिवर्तनों और स्थिरता के लिए परिवर्तन के केंद्र बिंदु पर आधारित हैं। भारत के कमोडिटी डेरिवेटिव्स एक्सचेंज के रूप में एमसीएक्स मानता है कि बाजार विकास का अगला चरण न केवल प्रोडक्ट नवाचार और नियामक विकास से, बल्कि जानकार और विश्लेषणात्मक रूप से कुशल बाजार प्रतिभागियों द्वारा भी संचालित होगा। एमसीएक्स-आईपीएफ कॉमक्वेस्ट वर्षों से एक साधारण क्विज से एक संरचित राष्ट्रीय मंच बन गया है, जो छात्रों को बाजार संकेतों की व्याख्या करने, हेजिंग फ्रेमवर्क समझने और जोखिम प्रबंधन की अनुशासनबद्धता का परीक्षण करने की चुनौती देता है। भागीदारी की बढ़ती गहराई और विविधता कमोडिटी बाजारों के मुख्य वित्तीय और आर्थिक चर्चाओं में बढ़ते एकीकरण को प्रतिबिंबित करती है। जैसे-जैसे वैश्विक अस्थिरता के चक्र तीव्र होते जा रहे हैं और भारत वैश्विक व्यापार तथा उत्पादन में अपनी भूमिका मजबूत कर रहा है, डेरिवेटिव्स विशेषज्ञता और बाजार बुद्धिमत्ता वाले पेशेवरों की मांग बढ़ेगी। कॉमक्वेस्ट जैसी पहलों के माध्यम से हम उस क्षमता पाइपलाइन को पोषित करने और अधिक लचीली तथा उन्नत कमोडिटी इकोसिस्टम के लिए उद्योग-शैक्षणिक इंटरफेस को मजबूत बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।"

फाइनलिस्टों ने आईआईएम-त्रिची, आईआईएम-उदयपुर, आईसीएफएआई-हैदराबाद, एनआईएसएम-मुंबई, वाम्निकॉम-पुणे, आईआईएफटी-कोलकाता, एक्सएलआरआई-जमशेदपुर और आईएमआई-नई दिल्ली सहित प्रमुख संस्थानों का प्रतिनिधित्व किया, जो इस पहल के व्यापक राष्ट्रीय पदचिह्न को दर्शाता है।

एमसीएक्स-आईपीएफ कॉमक्वेस्ट 2026 की 8वीं संस्करण के विजेता आईएमआई - नई दिल्ली के पार्थ बंसल रहे, जबकि प्रथम उपविजेता एनआईएसएम – मुंबई के रुशिकेश उगले और द्वितीय उपविजेता एक्सएलआरआई – जमशेदपुर के शुभम पसारी रहे। एमसीएक्स-आईपीएफ की टीम ने सभी विजेताओं को बधाई दी।

पश्चिम एशिया संकट के बीच भारत की ऊर्जा रणनीति कनाडा और ऑस्ट्रेलिया बने संभावित सहयोगी

(जीएनएस)। नई दिल्ली। पश्चिम एशिया में बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव ने वैश्विक ऊर्जा बाजार में नई अनिश्चितता पैदा कर दी है। इस स्थिति को देखते हुए India ने अपनी ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत बनाने के लिए कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस की आपूर्ति के वैकल्पिक स्रोतों पर ध्यान केंद्रित करना तेज कर दिया है। सरकार और ऊर्जा क्षेत्र से जुड़े विशेषज्ञों का मानना है कि मौजूदा हालात में ऊर्जा आपूर्ति को विविध बनाना अत्यंत आवश्यक हो गया है, ताकि किसी भी क्षेत्रीय संकट का देश की अर्थव्यवस्था और ऊर्जा जरूरतों पर गंभीर प्रभाव न पड़े। सूत्रों के अनुसार हाल ही में Israel और United States द्वारा Iran पर किए गए हमलों के बाद पश्चिम एशिया में तनाव तेजी से बढ़ गया है। इस घटनाक्रम ने पूरे क्षेत्र को अस्थिर बना दिया है और अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा आपूर्ति पर इसके संभावित प्रभाव को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं। ऊर्जा विशेषज्ञों का कहना है कि यदि क्षेत्रीय स्थिति और बिगड़ती है तो तेल और गैस की आपूर्ति में बाधा उत्पन्न हो सकती है, जिसका असर वैश्विक बाजारों और तेल आयात करने वाले देशों पर पड़ेगा।

विशेष चिंता उस महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग को लेकर है जिसे Strait of Hormuz कहा जाता है। यह जलडमरूमध्य दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण ऊर्जा मार्गों में से एक है, जहां से प्रतिदिन बड़ी मात्रा में कच्चा तेल और गैस विश्व के विभिन्न देशों तक पहुंचती है। भारत भी अपने आयातित कच्चे तेल का लगभग आधा हिस्सा इसी मार्ग से प्राप्त करता है। इसलिए इस क्षेत्र में किसी भी प्रकार की सैन्य या राजनीतिक अस्थिरता भारत की ऊर्जा आपूर्ति के लिए जोखिम पैदा कर सकती है।

इसी संभावित जोखिम को ध्यान में रखते हुए भारत अब अपने ऊर्जा आयात के स्रोतों को और अधिक विविध बनाने की दिशा में सक्रिय हो गया है। सरकारी सूत्रों के अनुसार कई देशों ने भारत को अतिरिक्त गैस और ऊर्जा आपूर्ति की पेशकश की है। इनमें Australia और Canada प्रमुख रूप से सामने आए हैं। दोनों देशों ने भारत के साथ ऊर्जा सहयोग को बढ़ाने में रुचि दिखाई है और भविष्य में दीर्घकालिक आपूर्ति समझौतों की संभावना पर भी चर्चा हो रही है। भारत पहले से ही अपनी ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए कई क्षेत्रों से कच्चा तेल और गैस आयात करता है। वर्तमान में प्रमुख आपूर्तिकर्ताओं में Russia, पश्चिम अफ्रीका के कई देश, अमेरिकी महाद्वीप के कुछ राष्ट्र, मध्य एशिया के ऊर्जा उत्पादक देश तथा खाड़ी क्षेत्र से बाहर स्थित मध्य पूर्व के कुछ देश शामिल हैं।

सप्ताह के दौरान क्रूड ऑयल वायदा में 1263 रुपये का ऊछालः सोना वायदा 1.69 लाख रुपये और चांदी वायदा 2.97 लाख रुपये के स्तर पर पहुँचा

(जीएनएस)। मुंबईः देश के अग्रणी कमोडिटी डेरिवेटिव्स एक्सचेंज एमसीएक्स पर कमोडिटी वायदा, ऑप्शंस और इंडेक्स फ्यूचर्स में 3561534.41 करोड़ रुपये का टर्नओवर दर्ज हुआ। कमोडिटी वायदाओं में 345812.35 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ, जबकि कमोडिटी ऑप्शंस में 3215714.66 करोड़ रुपये का नॉशनल टर्नओवर हुआ। बुलियन इंडेक्स बुलडेक्स का मार्च वायदा 39713 पॉइंट के स्तर पर बंद हुआ। कमोडिटी ऑप्शंस में कुल प्रीमियम टर्नओवर 55125.59 करोड़ रुपये का हुआ। आलौच्य अवधि के सप्ताह के दौरान कीमती धातुओं में सोना-चांदी के वायदाओं में 259947.14 करोड़ रुपये की खरीद बेच की गई। एमसीएक्स सोना अप्रैल वायदा सप्ताह के आरंभ में 160050 रुपये पर खूलकर, सप्ताह के दौरान इंट्रा-डे में ऊपर में 169880 रुपये और नीचे में 158716 रुपये पर पहुंचकर, 159709 रुपये के पिछले बंद के सामने सप्ताह के अंत में 36 रुपये या 0.02 फीसदी घटकर 159673 रुपये प्रति 10 ग्राम के भाव पर बंद हुआ। गोल्ड-गिनी मार्च वायदा सप्ताह के अंत में 1337 रुपये या 1.03 फीसदी की तेजी के संग 131395 रुपये प्रति 8 ग्राम हुआ। गोल्ड-पेटल मार्च वायदा 106 रुपये या 0.65 फीसदी की मजबूती के साथ सप्ताह के अंत में 16499 रुपये प्रति 1 ग्राम बंद हुआ। सोना-मिनी अप्रैल वायदा सप्ताह के आरंभ में 159306 रुपये पर खूलकर, सप्ताह के दौरान इंट्रा-डे में ऊपर में 169950 रुपये और नीचे में 157000 रुपये पर पहुंचकर, सप्ताह के अंत में 107 रुपये या 0.07 फीसदी तेज होकर यह कॉन्ट्रैक्ट 159813 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ। गोल्ड-टेन मार्च वायदा सप्ताह के आरंभ में प्रति 10 ग्राम 160599 रुपये पर खूलकर, सप्ताह के दौरान इंट्रा-डे में ऊपर में 172000 रुपये और नीचे में 157067 रुपये पर पहुंचकर, 160394 रुपये के पिछले बंद के सामने सप्ताह के अंत में 747 रुपये या 0.47 फीसदी की तेजी के संग 161141 रुपये प्रति 10 ग्राम के भाव पर पहुंचा।

कमोडिटी वायदाओं में 345812 करोड़ रुपये और कमोडिटी ऑप्शंस में 3215714 करोड़ रुपये का दर्ज हुआ साप्ताहिक टर्नओवर : सोना-चांदी के वायदाओं में 259947 करोड़ रुपये का हुआ साप्ताहिक कारोबार : बुलियन इंडेक्स बुलडेक्स फ्यूचर्स 39713 पॉइंट के स्तर पर

चांदी के वायदाओं में चांदी मई वायदा सप्ताह के आरंभ में 277500 रुपये के भाव पर खूलकर, सप्ताह के दौरान इंट्रा-डे में 297799 रुपये के उच्च और 257800 रुपये के नीचले स्तर को छूकर, 267953 रुपये के पिछले बंद के सामने सप्ताह के अंत में 5762 रुपये या 2.15 फीसदी की गिरावट के साथ 262191 रुपये प्रति किलो के भाव पर बंद हुआ। इनके अलावा चांदी-मिनी अप्रैल वायदा सप्ताह के अंत में 2748 रुपये या 1.01 फीसदी घटकर 268819 रुपये प्रति किलो के भाव पर बंद हुआ। जबकि चांदी-माइक्रो अप्रैल वायदा 2589 रुपये या 0.95 फीसदी गिरकर 269001 रुपये प्रति किलो सप्ताह के अंत में बंद हुआ।

मेटल वर्ग में 21971.23 करोड़ रुपये के ट्रेड दर्ज हुए। तांबा मार्च वायदा सप्ताह के अंत में 12.45 रुपये या 1.03 फीसदी औंधकर 1194.85 रुपये प्रति किलो पर बंद हुआ। जबकि जस्ता मार्च वायदा 5.65 रुपये या 1.73 फीसदी औंधकर सप्ताह के अंत में 321.3 रुपये प्रति किलो पर बंद हुआ। इसके सामने एल्यूमीनियम मार्च वायदा 18.5 रुपये या 5.93 फीसदी बढ़कर 330.6 रुपये प्रति किलो के भाव पर सप्ताह के अंत में बंद हुआ। जबकि सीसा मार्च वायदा सप्ताह के अंत में 95 पैसे या 0.5 फीसदी की नरमी के साथ 188.5 रुपये प्रति किलो के भाव पर बंद हुआ।

इन जिंसों के अलावा कारोबारियों ने एनर्जी सेगमेंट में 63837.14 करोड़ रुपये के सौदे किए। एमसीएक्स क्रूड ऑयल मार्च वायदा सप्ताह के आरंभ में 5950 रुपये के भाव पर खूलकर, सप्ताह के दौरान इंट्रा-डे में 7353 रुपये के उच्च और 5942 रुपये के नीचले स्तर को छूकर, सप्ताह के अंत में 1263 रुपये या 20.87 फीसदी की मजबूती के साथ 7316 रुपये प्रति बैरल बंद हुआ। जबकि क्रूड ऑयल-मिनी मार्च वायदा 1261 रुपये या 20.83 फीसदी की तेजी के संग सप्ताह के अंत में 7314 रुपये प्रति बैरल के भाव पर पहुंचा। इनके अलावा नैचुरल गैस मार्च वायदा सप्ताह के आरंभ में 258.5 रुपये के भाव पर खूलकर, सप्ताह के दौरान इंट्रा-डे में 295.1 रुपये के उच्च और 257.5 रुपये के नीचले स्तर को छूकर, 257.1 रुपये के पिछले बंद के सामने सप्ताह के अंत में 16.5 रुपये या 6.42 फीसदी की मजबूती के साथ 273.6 रुपये प्रति एमएमबीटीयू बंद हुआ। जबकि नैचुरल गैस-मिनी मार्च वायदा सप्ताह के अंत में 16.3 रुपये या 6.34 फीसदी तेज होकर यह कॉन्ट्रैक्ट 273.5 रुपये प्रति एमएमबीटीयू पर बंद हुआ।

कृषि जिंसों में मेंथा ऑयल मार्च वायदा सप्ताह के आरंभ में 956 रुपये के भाव पर खूलकर, सप्ताह के अंत में 7.7 रुपये या 0.81 फीसदी गिरकर 948.5 रुपये प्रति किलो हुआ। इलायची मार्च वायदा सप्ताह के अंत में 48 रुपये की गिरावट के साथ 2476 रुपये प्रति किलो पर बंद हुआ।

कारोबार की दृष्टि से एमसीएक्स पर आलौच्य अवधि के सप्ताह के दौरान सोना के विभिन्न अनुबंधों में 166312.51 करोड़ रुपये और चांदी के विभिन्न अनुबंधों में 93634.63 करोड़ रुपये की खरीद बेच की गई। इसके अलावा तांबा के वायदाओं में 16105.85 करोड़ रुपये, एल्यूमीनियम और एल्यूमीनियम-मिनी के वायदाओं में 3279.91 करोड़ रुपये, सीसा और सीसा-मिनी के वायदाओं में 77.33 करोड़ रुपये, जस्ता और जस्ता-मिनी के वायदाओं में 2508.14 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ।

इन जिंसों के अलावा क्रूड ऑयल और क्रूड ऑयल-मिनी के वायदाओं में 40586.97 करोड़ रुपये के ट्रेड दर्ज हुए। जबकि नैचुरल गैस और नैचुरल गैस-मिनी के वायदाओं में 23150.35 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ।

सप्ताह के अंत में ओपन इंटरेस्ट सोना के वायदाओं में 7894 लोट, सोना-मिनी के वायदाओं में 42794 लोट, गोल्ड-गिनी के वायदाओं में 15100 लोट, गोल्ड-पेटल के वायदाओं में 214155 लोट और गोल्ड-टेन के वायदाओं में 31905 लोट के स्तर पर था। जबकि चांदी के वायदाओं में 6349 लोट, चांदी-मिनी के वायदाओं में 14992 लोट और चांदी-माइक्रो वायदाओं में 53357 लोट के स्तर पर था। क्रूड ऑयल के वायदाओं में 15789 लोट और नैचुरल गैस के वायदाओं में 26791 लोट के स्तर पर था।

इंडेक्स फ्यूचर्स में बुलडेक्स मार्च वायदा 39935 पॉइंट पर खूलकर, सप्ताह के दौरान इंट्रा-डे में 41695 के उच्च और 39450 के नीचले स्तर को छूकर, सप्ताह के अंत में 224 पॉइंट बढ़कर 39713 पॉइंट के स्तर पर बंद हुआ।

गर्मी में पर्याप्त मात्रा में पीने के पानी का भंडार उपलब्ध

राज्य के मुख्य जलाशयों में वर्तमान स्थिति के अनुसार संग्रहीत कुल पानी का भंडार 72 प्रतिशत से अधिक

- गुजरात की जीवनरेखा समान सरदार सरोवर में 74 प्रतिशत से अधिक पानी का संग्रह
- राज्य में दक्षिण गुजरात के जलाशयों में सबसे अधिक 2.34 लाख एमसीएफटी पानी का भंडार
- पिछले वर्ष मार्च 2025 की तुलना में इस बार राज्य में 4.15 प्रतिशत अधिक पानी का भंडार उपलब्ध

(जीएनएस)। गांधीनगर : गुजरात में चालू वर्ष के मानसून में सार्वत्रिक एवं भारी वर्षा के परिणामस्वरूप राज्य के मुख्य जलाशयों अर्थात डैम में पर्याप्त मात्रा में पानी का भंडार उपलब्ध है। मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल के मार्गदर्शन और जल संसाधन एवं जल आपूर्ति मंत्री श्री ईश्वरसिंह पटेल के नेतृत्व में जल संचय के संबंध में सुचारू प्रबंधन के माध्यम से राज्य में दिन-प्रतिदिन पीने तथा सिंचाई के पानी की उपलब्धता बढ़ रही है।

जल संसाधन विभाग द्वारा बताया गया है कि राज्य में चालू वर्ष के मानसून में औसतन 128 प्रतिशत से अधिक वर्षा दर्ज की गई है। जिसके परिणामस्वरूप 5 मार्च 2026 की स्थिति के अनुसार राज्य के मुख्य जलाशयों में संग्रहीत कुल पानी का भंडार 6.46 लाख मिलियन क्यूबिक फीट (एमसीएफटी) अर्थात कुल पानी का भंडार 72 प्रतिशत से अधिक है। इस प्रकार पिछले वर्ष की तुलना में क्षेत्रवार कुल मिलाकर राज्य में 4.15 प्रतिशत अधिक तथा सरदार सरोवर जलाशय में भी पिछले वर्ष की तुलना में 1.63 प्रतिशत अधिक पानी का भंडार संग्रहीत है। इसलिए राज्य में आगामी गर्मी में पर्याप्त मात्रा में पीने का पानी उपलब्ध रहेगा।

इसके अलावा, गुजरात की जीवनरेखा समान सरदार सरोवर योजना में वर्तमान स्थिति के अनुसार 74 प्रतिशत से अधिक अर्थात 2.47 लाख एमसीएफटी पानी का भंडार संग्रहीत है। राज्य में सबसे अधिक दक्षिण गुजरात में 2.34 लाख से अधिक एमसीएफटी पानी का भंडार जलाशयों में संचित है। इसके अलावा मध्य गुजरात में 65,179 एमसीएफटी, उत्तर गुजरात में 41,842 एमसीएफटी पानी का भंडार संग्रहीत है। सौराष्ट्र में 53,621 और कच्छ क्षेत्र में 4,392 एमसीएफटी पानी का भंडार संग्रहीत है। इस प्रकार राज्य में कुल 6,46,556 एमसीएफटी अर्थात 72.49 प्रतिशत पानी का भंडार संग्रहीत है। सूची में बताया गया है कि पिछले वर्ष 5 मार्च 2025 की तुलना में स्थिति के अनुसार राज्य में क्षेत्रवार उत्तर गुजरात में 27,847 एमसीएफटी, मध्य गुजरात में 57,882 एमसीएफटी, दक्षिण गुजरात में 2,24,182 एमसीएफटी, सौराष्ट्र में 52,264 एमसीएफटी और कच्छ क्षेत्र में 5,332 एमसीएफटी पानी का भंडार संग्रहीत था। इसके अलावा, सरदार सरोवर जलाशय में 2,41,952 एमसीएफटी अर्थात 72.42 प्रतिशत पानी का भंडार उपलब्ध था। इस प्रकार राज्य में पिछले वर्ष कुल 6,09,459 एमसीएफटी अर्थात 68.34 प्रतिशत पानी का भंडार उपलब्ध था।

उल्लेखनीय है कि राज्य में सबसे अधिक सौराष्ट्र में 141 जलाशय, उत्तर गुजरात में 15, मध्य गुजरात में 17, दक्षिण गुजरात में 13, कच्छ में 20 तथा सरदार सरोवर सहित गुजरात में कुल 207 जलाशय-डैम स्थित हैं।

सुरक्षित एवं कुशल रेल संचालन के लिए जेतलसर में रनिंग स्टाफ हेतु आधुनिक विश्राम कक्ष विकसित

(जीएनएस)। पश्चिम रेलवे के भावनगर मंडल द्वारा सुरक्षित एवं कुशल रेल संचालन को सुदृढ़ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल करते हुए जेतलसर जंक्शन स्टेशन पर रनिंग स्टाफ (चालक दल एवं ट्रेन मैनेजर) के लिए आधुनिक सुविधाओं से युक्त विश्राम कक्ष विकसित किया गया है। जेतलसर स्टेशन ढसा–जेतलसर, राजकोट–सोमनाथ तथा वांसजालिया–जेतलसर खंडों का एक महत्वपूर्ण जंक्शन स्टेशन है, जहाँ रनिंग स्टाफ के ऑन-ड्यूटी एवं ऑफ-ड्यूटी करने की सुविधा उपलब्ध है। पूर्व में यहाँ चालक दल और ट्रेन मैनेजरों को हो रही कठिनाइयों को देखते हुए पर्याप्त विश्राम व्यवस्था उपलब्ध कराकर उनकी कठिनाइयों को दूर किया गया है।

मंडल रेल प्रबंधक श्री दिनेश वर्मा के मार्गदर्शन में जेतलसर जंक्शन पर मूलभूत सुविधाओं से युक्त एक आधुनिक विश्राम कक्ष विकसित किया गया है। वर्तमान में इस विश्राम कक्ष में एयर कंडीशनिंग, वाटर गीजर सहित अन्य आवश्यक सुविधाएँ उपलब्ध कराई गई हैं । इसके साथ ही चालक दल और ट्रेन मैनेजरों के लिए भोजन (डाइनिंग) की सुविधा भी इसी विश्राम कक्ष में उपलब्ध कराई जाएगी।

इस संबंध में जानकारी देते हुए वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक श्री अतुल कुमार त्रिपाठी ने बताया कि जेतलसर जंक्शन पर इस विश्राम कक्ष की स्थापना से इस खंड में कार्यरत चालक दल और ट्रेन मैनेजरों को पर्याप्त आराम की सुविधा प्राप्त होगी। इससे न केवल कर्मचारियों के कल्याण में वृद्धि होगी, बल्कि रेल परिचालन की सुरक्षा, कार्यकुशलता तथा निर्धारित ड्यूटी घंटों के पालन को सुनिश्चित करने में भी महत्वपूर्ण सहायता मिलेगी।

सोलधरा गांव की 'लखपति दीदी', जिन्होंने गांव की भूमि पर आत्मनिर्भरता का एक नया इतिहास रचा : वीजीआरसी दक्षिण गुजरात में बनेगा आत्मनिर्भरता और महिला सशक्तिकरण का उदाहरण

▸▸ ग्रामीण विकास से वैश्विक फलक तक : दक्षिण गुजरात की आत्मनिर्भर महिला उद्यमी अस्मिताबेन पटेल आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करने में दे रही हैं योगदान

▸▸ घर पर ही शहद उत्पादन शुरू किया और आज 10 लाख से अधिक की आय

(जीएनएस)। गांधीनगर : 'नारी शक्ति ही समाज की सच्ची शक्ति' इस कहावत को सही मायने में सार्थक करती हैं गुजरात की चिखली तहसील के सोलधरा गांव की अस्मिताबेन अशोकभाई पटेल। आज अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर अस्मिताबेन और उनके आत्मनिर्भरता के सफर के बारे में जानकर ताज्जुब होगा कि एक किसान परिवार से आने के बावजूद आज उन्होंने अपना उद्योग संचालित करते हुए स्वयं के साथ 10 दूसरी महिलाओं को भी आत्मनिर्भर बनाया है, जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री के 'आत्मनिर्भर भारत मिशन' को साकार करता है।

उल्लेखनीय है कि अप्रैल 2026 में सूरत में वाइब्रेंट गुजरात रीजनल कॉन्फ्रेंस (वीजीआरसी) दक्षिण गुजरात का आयोजन होने जा रहा है। इसमें स्थानीय महिला स्वयं सहायता समूहों और ग्रामीण उद्यमियों को वैश्विक बाजार के साथ जोड़ने पर बल दिया जाएगा। इस मंच के माध्यम से अस्मिताबेन जैसी

महिला उद्यमियों को अपनी क्षमता प्रदर्शित करने का एक नया अवसर मिलेगा। मधुमक्खी पालन से आत्मनिर्भरता की शुरुआत

गुजरात की चिखली तहसील के सोलधरा गांव में जन्मीं अस्मिताबेन अशोकभाई पटेल का लालन-पालन एक किसान परिवार में हुआ। खेती और पशुपालन का ज्ञान उन्हें बचपन से ही घुट्टी में मिला। आर्ट टीचर डिप्लोमा (एटीडी) की पढ़ाई के दौरान ही पिता की मौत का आघात सहन करना पड़ा, लेकिन प्रगतिशील सास-ससूर और खुद का आत्मविश्वास ही उनकी ढाल बन गया। उन्होंने विवाह के बाद बीए की डिग्री हासिल की, और इस प्रकार ज्ञान और स्वयं के उत्कर्ष की यात्रा निर्बाध चलती रही। खेती की आय सीमित थी, घर चलाना भी मुश्किल था। इस मुश्किल दौर में 2020-11 में अस्मिताबेन ने मधुमक्खी पालन का कोर्स पूरा किया। उन्होंने घर पर ही शहद का उत्पादन शुरू किया और उसे बाजार में बेचा। 2014 में नवसारी कृषि विश्वविद्यालय से बेकरी कोर्स किया। यह उत्साह और जुनून ही उनकी पहचान बन गया।

'सह्याद्री सखी मंडल' – 10 महिलाएं और 1 सपना

2015 में अस्मिताबेन ने 10 महिलाओं के साथ ग्राम विकास अधिकारियों के मार्गदर्शन में 'सह्याद्री सखी मंडल' की स्थापना की। शुरुआत आम, नींबू और करौंदा का अचार और मौसमी उत्पाद बनाने की गतिविधियों से हुई।

मिशन मंगलम के अंतर्गत 15,000 रुपए का रिवॉल्विंग फंड मिलने पर रागी (नागली) से बने उत्पाद, पापड़, बिस्कुट और आटे का उत्पादन शुरू हुआ। इन उत्पादों को स्थानीय, जिला और प्रादेशिक स्तर के कृषि मेलों में प्रदर्शित करने के साथ ही उनकी बिक्री की गई। बाद में, व्यावसायिक उद्देश्य से 2,00,000 रुपए का ऋण लिया और हल्दी प्रोसेसिंग और पीसने की मशीन खरीदी, जिससे प्राकृतिक हल्दी पाउडर का उत्पादन शुरू हुआ।

आज, सह्याद्री सखी मंडल की दूसरी महिलाओं के साथ मिलकर अस्मिताबेन ने प्राकृतिक और हाथ से बने खाद्य पदार्थों का उत्पादन शुरू कर दिया है। आज, उनके स्वयं सहायता समूह की महिलाएं घर बैठे शहद पैकिंग और प्रोसेसिंग का कामकाज संभालती हैं, जबकि अन्य महिलाएं अचार, आंवले की कैंडी, नागली की वेफर्स और बांस के हस्तशिल्प उत्पाद बनाती और बेचती हैं। इन उत्पादों को स्थानीय बाजार में बेचने के साथ-साथ राज्य और राष्ट्रीय स्तर के सरस मेलों में भी भव्य रूप से प्रदर्शित किया जाता है।

आज अस्मिताबेन की सालाना आय 10.20 लाख रुपए है यानी आज वे न केवल एक लखपति दीदी हैं, बल्कि उनके गांव और समुदाय में एक सम्मानित और मार्गदर्शक महिला हैं। वे अपनी इस सफलता का श्रेय मिशन मंगलम योजना और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के गांवों की महिलाओं तक लाभ पहुंचाने के लिए किए गए प्रयासों को देती हैं।

राष्ट्रीय स्तर पर मिली मान्यता

अस्मिताबेन को राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) के तहत उनके कार्य-प्रदर्शन के लिए अनेक पुरस्कार मिले हैं। उन्हें माननीय प्रधानमंत्री से तीन बार मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। उन्हें गुजरात सरकार की ओर से 'कृषि रत्न पुरस्कार' प्राप्त हुआ है, साथ ही अप्रैल 2015 में जिला स्तर पर कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन एजेंसी – आत्मा अवॉर्ड भी मिला है।

सह्याद्री की विरासत

अस्मिताबेन पटेल का सफर केवल एक व्यक्तिगत सफलता नहीं है, यह ग्रामीण अर्थव्यवस्था, महिला सशक्तिकरण और टिकाऊ विकास का मॉडल है। सह्याद्री सखी मंडल ने स्थानीय कच्चे माले, पारंपरिक कुशलता और प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके रोजगार सृजन की एक अनूठी मिसाल कायम की है।

अस्मिताबेन गर्व से कहती हैं, "जिस प्रकार एक मजबूत पेड़ की जड़ें एकता में होती हैं और उसकी शाखाएं अवसर मिलने पर फैलती जाती हैं, उसी प्रकार हमारा यह समूह भी आज मजबूती से खड़ा है।" स्वरोजगार का उनका यह सफर साबित करता है कि जब महिलाएं एकजुट होती हैं, तब उनका विकास घर से समाज तक और वहां से देश के प्रत्येक कोने तक पहुंचता है। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर अस्मिताबेन जैसी 'लखपति दीदीओं' को सलाम, जो गांव की धरती से उठकर सह्याद्री जैसी अडिग शक्ति बन गई हैं और समाज में परिवर्तन का एक नया अध्याय लिख रही हैं।

वडोदरा में एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग पर राष्ट्रीय सेमिनार, भविष्य के औद्योगिक इकोसिस्टम पर हुआ मंथन

(जीएनएस)। गुजरात के औद्योगिक शहर Vadodara में एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में संभावनाओं और नई तकनीकों पर चर्चा के लिए एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय स्तर का सेमिनार आयोजित किया गया। यह एक दिवसीय सेमिनार Gujarat State Transformation Institution (GRIT) और Gujarat Industrial Development Corporation (GIDC) की संयुक्त पहल से आयोजित हुआ। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य गुजरात को एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर अग्रणी बनाने की दिशा में उद्योग, नीति और तकनीक से जुड़े विशेषज्ञों को एक साझा मंच प्रदान करना था। सेमिनार में उद्योग जगत, नीति निर्माताओं, निवेशकों और तकनीकी विशेषज्ञों ने भाग लिया और भविष्य की औद्योगिक दिशा पर अपने विचार साझा किए। कार्यक्रम के दौरान यह स्पष्ट किया गया कि वैश्विक प्रतिस्पर्धा के दौर में पारंपरिक उत्पादन प्रणालियों से आगे बढ़कर उच्च मूल्य आधारित और तकनीक संचालित मैन्युफैक्चरिंग की ओर बढ़ना समय की आवश्यकता है। इसी उद्देश्य से गुजरात सरकार आधुनिक औद्योगिक पारिस्थितिकी तंत्र को विकसित करने की दिशा में कई कदम उठा रही है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए GRIT की मुख्य कार्यकारी अधिकारी S. Aparna ने कहा कि गुजरात सरकार इनोवेशन और अत्याधुनिक तकनीकों के माध्यम से भविष्य के लिए तैयार औद्योगिक ढांचा विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि "Developed Gujarat @2047" के लक्ष्य को हासिल करने के लिए राज्य को पारंपरिक मैन्युफैक्चरिंग से आगे बढ़ते हुए हाई-वैल्यू प्रोडक्ट्स और टेक्नोलॉजी आधारित उत्पादन को बढ़ावा देना होगा। उन्होंने औद्योगिक क्लस्टर्स में इंडस्ट्री 4.0 के समावेशन, कौशल विकास और तकनीकी उन्नयन पर विशेष बल दिया।

उन्होंने यह भी बताया कि डिजिटल तकनीकों और स्वचालन के बढ़ते उपयोग से उत्पादन क्षमता और गुणवत्ता दोनों में सुधार संभव है। ऐसे में उद्योगों को नई तकनीकों को अपनाने के लिए तैयार रहना होगा, ताकि वे वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्धी बने रह सकें। उन्होंने उद्योग जगत और शैक्षणिक संस्थानों के बीच सहयोग को भी महत्वपूर्ण बताया, जिससे नवाचार और अनुसंधान को बढ़ावा मिल सके।

कार्यक्रम में विशेष अतिथि के रूप में उपस्थित वडोदरा नगर निगम के आयुक्त Arun Mahesh Babu ने शहर की रणनीतिक

स्थिति और औद्योगिक विकास की संभावनाओं पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि वडोदरा में विभिन्न प्रकार के उद्योगों की मजबूत उपस्थिति इसे निवेशकों के लिए एक आकर्षक केंद्र बनाती है। उन्होंने बताया कि शहर से होकर गुजरने वाला डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर और प्रस्तावित हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर, जिसे आमतौर पर बुलेट ट्रेन परियोजना कहा जाता है, आने वाले समय में औद्योगिक विकास के लिए गेम-चेंजर साबित हो सकता है। उन्होंने यह भी कहा कि इस प्रकार के कार्यक्रम उद्योगों और नीति निर्माताओं के बीच संवाद को मजबूत करने में मदद करते हैं। साथ ही उन्होंने इस सेमिनार को वडोदरा में प्रस्तावित 'रीजनल वाइब्रेंट समिट' का प्रारंभिक मंच बताया, जो भविष्य में राज्य में निवेश और औद्योगिक विकास को नई दिशा देने में सहायक होगा। सेमिनार के दौरान उद्योग और तकनीक से जुड़े विशेषज्ञों ने एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग के विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की। वैश्विक परामर्श कंपनी KPMG के पार्टनर Abhishek Gupta ने आधुनिक तकनीकों के उपयोग पर विशेष प्रस्तुति दी। उन्होंने बताया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और डिजिटल ट्विन जैसी तकनीकों के माध्यम से उत्पादन क्षमता बढ़ाई जा सकती है और लागत को भी प्रभावी ढंग से कम किया जा सकता है। उन्होंने यह भी कहा कि डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन केवल तकनीकी बदलाव नहीं है, बल्कि यह उद्योगों की कार्यशैली और प्रबंधन प्रणाली को भी पूरी तरह बदल देता है। यदि उद्योग इन तकनीकों को सही तरीके से अपनाते हैं तो वे वैश्विक स्तर पर अधिक प्रतिस्पर्धी बन सकते हैं।

कार्यक्रम के अंतर्गत आयोजित पैनल चर्चा में कई प्रतिष्ठित औद्योगिक कंपनियों के विशेषज्ञों ने भाग लिया और वैश्विक रुझानों पर अपने विचार साझा किए। इस चर्चा में GE Aerospace के उमा महेश्वर डी., Larsen & Toubro की दिव्या भट्ट, MG Motor India की नेहा जैन तथा Honeywell के डॉ. बुबथी मुरुगनाथम सहित कई विशेषज्ञ शामिल हुए। इन विशेषज्ञों ने एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग में मानव संसाधन विकास, कौशल उन्नयन और नई तकनीकों की भूमिका पर विस्तार से चर्चा की। पैनल चर्चा के दौरान यह भी बताया गया कि आने वाले समय में उद्योगों को केवल तकनीकी नवाचार पर ही नहीं, बल्कि कुशल मानव संसाधन तैयार करने पर भी समान रूप से ध्यान देना होगा। नई तकनीकों के प्रभावी उपयोग के लिए प्रशिक्षित और दक्ष कार्यबल की आवश्यकता होगी, जो इंडस्ट्री 4.0 की जरूरतों के अनुरूप काम कर सके।

कार्यक्रम में कई अन्य औद्योगिक संगठनों और कंपनियों के प्रतिनिधियों ने भी भाग लिया। इनमें SEE लिंकेज, कॉन्सेप्ट बिजनेस एक्सीलेंस, Alstom ग्रुप और फिस्कल ऑक्स क्लाउड जैसे संगठनों के प्रतिनिधियों ने डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के माध्यम से औद्योगिक परिवर्तन का रोडमैप प्रस्तुत किया। इन प्रस्तुतियों में यह बताया गया कि किस प्रकार नई तकनीकों के उपयोग से उत्पादन प्रक्रिया को अधिक स्मार्ट, कुशल और टिकाऊ बनाया जा सकता है। इस राष्ट्रीय सेमिनार में प्रशासन और उद्योग जगत के कई वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित रहे। कार्यक्रम में जिला कलेक्टर Anil Dhameliya, GIDC के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर Bharat Joshi सहित उद्योग क्षेत्र के कई अधिकारी, इंडस्ट्री एसोसिएशन के प्रतिनिधि और निवेशक बड़ी संख्या में शामिल हुए। उनकी उपस्थिति ने यह संकेत दिया कि गुजरात में एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में सहयोग और निवेश की संभावनाएं तेजी से बढ़ रही हैं। कुल मिलाकर यह सेमिनार गुजरात के औद्योगिक भविष्य को लेकर एक महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है। इसमें हुई चर्चाओं और प्रस्तुतियों से यह स्पष्ट हुआ कि यदि उद्योग, सरकार और तकनीकी संस्थान मिलकर काम करें तो गुजरात को एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर अग्रणी बनाया जा सकता है।

वैश्विक तनाव का असर: भागलपुर के सिल्क उद्योग पर संकट के बादल

(जीएनएस)। बिहार के प्रसिद्ध रेशम नगरी Bhagalpur का सिल्क उद्योग इन दिनों गंभीर चुनौतियों का सामना कर रहा है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव और वैश्विक व्यापार में आई अनिश्चितता का सीधा प्रभाव अब स्थानीय उद्योगों पर भी दिखाई देने लगा है। हाल ही में लगभग 25 करोड़ रुपये का बड़ा निर्यात ऑर्डर रद्द होने से भागलपुर के बुनकरों और व्यापारियों को भारी आर्थिक झटका लगा है। यह घटना केवल एक व्यापारिक नुकसान नहीं है, बल्कि उस पारंपरिक उद्योग के लिए चिंता का विषय बन गई है, जिसने दशकों से देश-विदेश में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई है। स्थानीय व्यापारियों के अनुसार अंतरराष्ट्रीय बाजार में पैदा हुई अस्थिरता ने विदेशी खरीदारों को सावधानी बरतने के लिए मजबूर कर दिया है। विशेष रूप से United States और Iran के बीच बढ़ते तनाव के कारण वैश्विक व्यापारिक माहौल प्रभावित हुआ है। ऐसी स्थिति में कई अंतरराष्ट्रीय आयातकों ने नए ऑर्डर देने से फिलहाल परहेज करना शुरू कर दिया है और कुछ पहले से तय ऑर्डर भी रोक दिए हैं। इसका सीधा असर भागलपुर के रेशम उद्योग पर पड़ा है, जहां तैयार किए गए सिल्क उत्पाद बड़ी मात्रा में विदेशी बाजारों में निर्यात किए जाते हैं।

भागलपुर का सिल्क उद्योग केवल बिहार ही नहीं, बल्कि पूरे देश की पारंपरिक हस्तशिल्प विरासत का महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। यहां के बुनकर पीढ़ियों से रेशमी वस्त्र तैयार करने की कला को जीवित रखे हुए हैं। इस क्षेत्र में हजारों परिवार सीधे या परोक्ष रूप से सिल्क उद्योग से जुड़े हुए हैं। जब निर्यात के बड़े ऑर्डर अचानक रद्द हो जाते हैं तो इसका प्रभाव केवल व्यापारियों तक सीमित नहीं रहता, बल्कि बुनकरों, मजदूरों और उनसे जुड़े छोटे व्यवसायों तक भी पहुंचता है।

हाल के दिनों में भागलपुर की कई बुनकर बस्तियों में असामान्य सन्नाटा देखने को मिला है। जिन करघों की आवाज कभी पूरे इलाके में गूंजती थी, वे अब कई जगह बंद पड़े दिखाई दे रहे हैं। बुनकरों का कहना है कि ऑर्डर रद्द होने से उत्पादन धीमा पड़ गया है और कई लोगों के सामने रोजगार का संकट खड़ा हो गया है। तैयार माल के लिए बाजार न मिलने के कारण उत्पादन रोकना या सीमित करना मजबूरी बन गया है।

स्थानीय बुनकरों का कहना है कि यह उद्योग पिछले कुछ वर्षों से लगातार कठिन दौर से गुजर रहा है। COVID-19 महामारी के दौरान वैश्विक व्यापार लगभग ठप हो गया था, जिससे सिल्क उद्योग को भारी नुकसान उठाना पड़ा था। महामारी के बाद व्यापार धीरे-धीरे पटरी पर लौटने की उम्मीद जगी थी, लेकिन अब अंतरराष्ट्रीय संघर्ष और वैश्विक आर्थिक अस्थिरता ने फिर से स्थिति को जटिल बना दिया है।

बुनकर हेमंत कुमार और आलोक कुमार जैसे स्थानीय कारीगरों का कहना है कि सिल्क उद्योग के सामने चुनौतियां लगातार बढ़ती जा रही हैं। पहले महामारी के कारण बाजार बंद हुए, फिर कच्चे माल की कीमतें बढ़ीं और अब अंतरराष्ट्रीय तनाव के कारण निर्यात बाजार प्रभावित हो रहा है। इन परिस्थितियों ने कई छोटे बुनकरों को आर्थिक संकट में डाल दिया है, क्योंकि उनकी आय का मुख्य स्रोत यही उद्योग है। भागलपुर के सिल्क उद्योग का एक बड़ा निर्यात बाजार पड़ोसी देश Bangladesh भी रहा है। यहां तैयार किए गए रेशमी कपड़े बड़ी मात्रा में बांग्लादेश भेजे जाते थे, जहां से उनका आगे भी व्यापार होता था। लेकिन पिछले कुछ समय में वहां के बाजार में आई मंदी और व्यापारिक बदलावों के कारण यह निर्यात भी काफी कम हो गया है। इससे स्थानीय उद्योग की निर्भरता अन्य विदेशी बाजारों पर बढ़ गई थी, जो अब अंतरराष्ट्रीय तनाव के कारण प्रभावित हो रहे हैं। भागलपुर के रेशमी वस्त्र अपनी विशेष गुणवत्ता और विविधता के लिए जाने जाते हैं। यहां तसर, मुगा, कोसा, मटका, मलवरी और अरंडी जैसे कई प्रकार के रेशमी कपड़े तैयार किए जाते हैं। इनकी बनावट, रंगों की विविधता और पारंपरिक डिजाइन के कारण इनकी मांग देश के साथ-साथ अंतरराष्ट्रीय बाजारों में भी रही है। विदेशी ग्राहक विशेष रूप से भागलपुर के सिल्क की प्राकृतिक चमक और हस्तनिर्मित गुणवत्ता को पसंद करते हैं।

सत्यमेव जयते
गुजरात सरकार

सशक्त और स्वस्थ महिला, समृद्ध समाज

महिला एवं बाल विकास विभाग के लिए कुल ₹7690 करोड़ का प्रावधान।

गंगा स्वरूपा आर्थिक सहायता योजना के अंतर्गत ₹2848 करोड़ का प्रावधान।

आंगनवाड़ी कार्यकर्ता/तेड़ागर और मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता बहनों के मानदेय के लिए ₹1128 करोड़ का प्रावधान।

पूरक पोषण योजना के अंतर्गत 3 से 6 वर्ष के बच्चों को आंगनवाड़ी में गरम नाश्ता और भोजन देने के साथ-साथ बच्चों, किशोरियों और गर्भवती व धात्री माताओं को 'टेक होम राशन' उपलब्ध कराने के लिए ₹972 करोड़ का प्रावधान।

दूध संजीवनी योजना के तहत फोर्टिफाइड दूध देने के लिए ₹205 करोड़ का प्रावधान।

व्हाली दीकरी योजना के अंतर्गत ₹245 करोड़ का प्रावधान।

दो हजार आंगनवाड़ी केंद्रों के निर्माण के लिए ₹360 करोड़ का प्रावधान।

विकसित भारत
गुजरात बजट 2026-27
विकसित गुजरात

बेटी के जन्म से लेकर माताओं के पोषण, सम्मान और सुरक्षा तक, राज्य सरकार हर कदम पर मातृशक्ति के साथ खड़ी है।
महिला एवं बाल विकास के लिए आवंटित ₹7,690 करोड़ का यह बजट 'सशक्त और स्वस्थ महिला, समृद्ध समाज' के हमारे संकल्प को चरितार्थ करेगा।
- श्री हर्ष संघवी, माननीय उपमुख्यमंत्री, गुजरात